INTERVIEW PREPARATION

CURRENT AFFAIRS

By Shridhant Joshi Sir

MD, Kautilya Academy

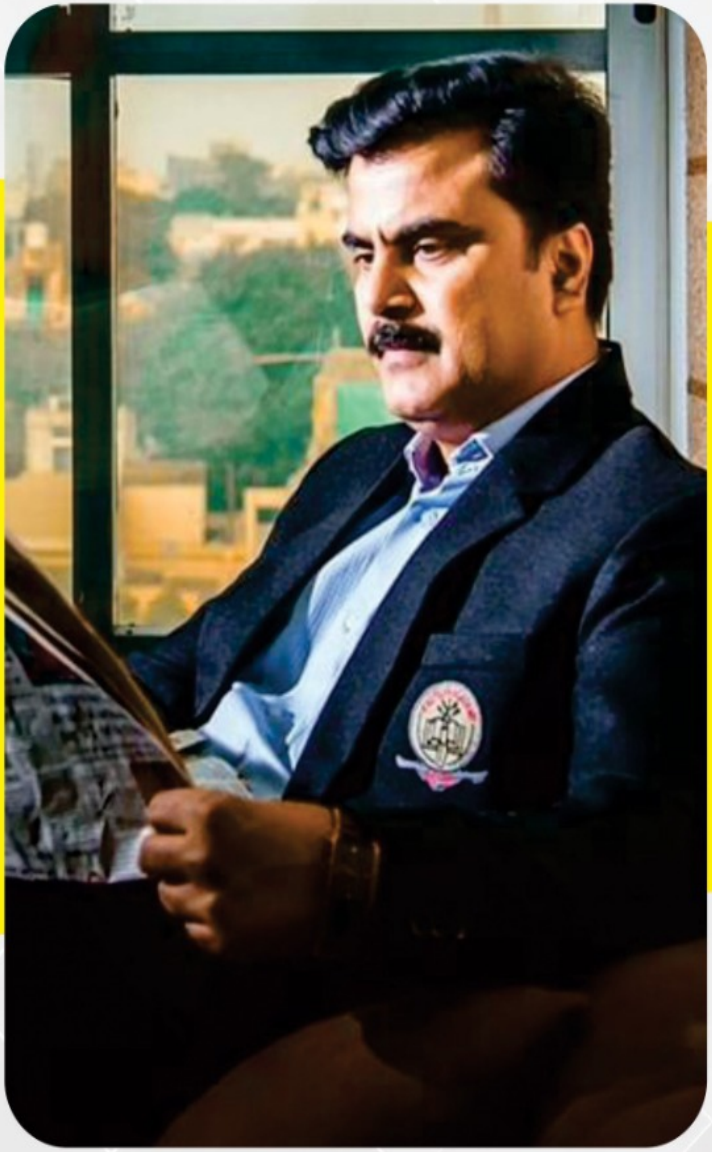

कौटिल्य एकेडमी

IAS, IPS, IRS, MPPSC & OTHER STATES PCS

www.kautilyaacademy.com, www.kautilyaacademy.in

Mob : 9425068121, 9893929541

और बढ़ेंगी पेटीएम की मुश्किलें

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

डिजिटल लेनदेन में देश की प्रमुख कंपनी पेटीएम की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। एक तरफ जहां वित्त मंत्रालय ने कंपनी के खिलाफ ईडी जांच शुरू कराने के संकेत दिए हैं, वहीं उच्च स्तर पर पेटीएम पेमेंट बैंक के बैंकिंग लाइसेंस को रद करने की संभावना पर भी विचार हो रहा है। 31 जनवरी को आरबीआइ ने पेटीएम समूह के पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड की लगभग सभी वित्तीय गतिविधियों पर 29 फरवरी, 2024 के बाद रोक लगाने का निर्देश दिया है। हालांकि पेटीएम की तरफ से ग्राहकों को यह भरोसा दिया जा रहा है कि उनका डिजिटल पेमेंट एप काम करता रहेगा।

आरबीआइ ने अपने निर्देश में यह बताया है कि पहले विस्तृत आडिट रिपोर्ट में और उसके बाद बाहरी एजेंसियों से कराए गई जांच में यह बात सामने आई है कि पेटीएम बैंक में नियमों के अनुपालन में लगातार खामियां पाई गई हैं। इन खामियों के बारे में कोई ज्यादा जानकारी तो नहीं दी गई है लेकिन सूत्रों का कहना है कि मुख्य अनियमितता यह पाई गई है कि एक ही पैन नंबर पर एक हजार से अधिक खाते खोले गए और एक ही खाते से सैकड़ों लोगों को भुगतान किया गया है। ये वित्तीय लेन-देन करोड़ों का है, जिससे यह गैर कानूनी तरीके से नकदी हस्तांतरण का मामला बनता है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह संगठित गिरोहों की तरफ से किया गया है या फिर व्यक्तिगत स्तर पर कालेधन को खपाने व एजेंसियों की नजर से बचने के लिए किया गया है। लेकिन निश्चित तौर पर यह मनी लांड्रिंग का मामला है। उधर, पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन97 कंम्यूनिकेशन का कहना है कि कंपनी या सीईओ विजय शेखर शर्मा के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में कोई ईडी जांच नहीं हो रही है। हम भारतीय कानूनों का पालन करते हैं और रेगुलेटरी आदेशों को अत्यंत गंभीरता से लेते हैं।

ईडी कर सकती है मनी लांड्रिंग के मामलों की जांच, पेमेंट बैंक के लाइसेंस से भी धोना पड़ सकता है हाथ

1000 से अधिक खाते खोले एक ही पैन पर, एक ही खाते से सैकड़ों को भुगतान किया गया

29 के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सभी वित्तीय गतिविधियों पर रोक का आरबीआइ ने दिया है निर्देश

पीएमओ, गृह व वित्त मंत्रालय के अफसरों के बीच पेटीएम की स्थिति पर हुई वार्ता पेज>>10

कौटिल्य अकैडमी

स्नातक के साथ छात्र 16 प्रमुख क्षेत्रों में कर सकेंगे शोध और इंटर्नशिप

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- **यूजीसी ने शोध और इंटर्नशिप करने वाले छात्रों के लिए जारी की गाइडलाइन**
- **आइटी, एआइ सहित देश की जरूरत से जुड़े 16 क्षेत्रों को इसके लिए किया चिह्नित**

विश्वविद्यालयों में शुरू किए गए चार वर्षीय स्नातक कोर्सों में दाखिला लेने वाले छात्रों को स्नातक स्तर पर ही शोध और इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इसे लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। हालांकि इस दौरान छात्रों को सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में शोध करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जो देश के विकास को रफ्तार देने के लिए जरूरी होंगे। इसके तहत फिलहाल एआइ, आइटी व पर्यटन सेक्टर सहित 16 प्रमुख क्षेत्रों को चिह्नित किया गया है। खास बात यह है इन क्षेत्रों में शोध करने वाले छात्रों को स्नातक आनर्स के साथ शोध (आनर्स विद रिसर्च) की डिग्री मिलेगी।

यूजीसी ने इस गाइडलाइन के साथ ही सभी विश्वविद्यालयों से अपने यहां इसके लिए जरूरी ढांचा तैयार करने को कहा है। इसके तहत एक नोडल अधिकारी की तैनाती है, जिसकी शोध और इंटर्नशिप जैसे कामों में रूचि हो। इसके साथ ही

यूजीसी का छात्र हितैषी कदम।

संस्थानों से स्थानीय स्तर पर चिह्नित किए गए क्षेत्रों के संबंध में एक सर्वे कराने को भी कहा है ताकि वह उनकी जरूरतों को पहचान सकें और उसे मजबूती भी दे सकें। यूजीसी के मुताबिक छात्रों को शोध व इंटर्नशिप के लिए जरूरी क्रेडिट अंक भी दिए जाएंगे। इस दौरान इंटर्नशिप करने पर दो से चार क्रेडिट अंक तक मिलेंगे जबकि शोध करने पर 12 क्रेडिट अंक मिलेंगे। इस दौरान एक क्रेडिट अंक के लिए छात्रों को कम से कम 30 घंटे तक उस क्षेत्र में देना होगा। गौरतलब है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत छात्रों को स्नातक स्तर पर ही शोध के लिए प्रोत्साहित करने को चार वर्षीय स्नातक प्रोग्राम में इसे जोड़ा गया है। अभी तक किसी भी छात्र को शोध कार्यों से जुड़ने के लिए उसका परास्नातक (पोस्ट ग्रेजुएट) होना जरूरी होता था।

इन क्षेत्रों में कर सकेंगे शोध और इंटर्नशिप : यूजीसी ने स्नातक स्तर पर छात्रों को शोध और इंटर्नशिप से जोड़ने के लिए जिन 16 प्रमुख क्षेत्रों को चुना है, उनमें एआइ, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आइटी, व्यापार व कृषि क्षेत्र, इकोनमी-बैंकिंग क्षेत्र, लाजिस्टिक, हैंडीक्राफ्ट, हेल्थ केयर और लाइफ साइंस, पर्यटन, मानवाधिकार, संचार, शिक्षा, पर्यावरण, मध्यम व छोटे उद्योग, खेल-फिजिकल एजुकेशन आदि शामिल हैं।

अपने अतीत को मिटाकर कभी प्रगति नहीं कर सकता कोई देश : मोदी

- कहा- आजादी के बाद सत्ता में रहने वाले लोग पूजास्थलों का महत्व नहीं समझ सके, उन्हें आती थी अपनी संस्कृति पर शर्म
- पिछले 10 वर्षों में बदली स्थिति, पहले बड़े-बड़े संस्थान सिर्फ बड़े शहरों में होते थे, हम विकास की नीति पर कर रहे काम
- मां कामाख्या दिव्य परियोजना समेत असम में किया 11,600 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास

गुवाहाटी, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को दावा किया कि आजादी के बाद जो लोग लंबे समय तक सत्ता में रहे, वे पूजास्थलों की महत्ता को नहीं समझ सके और उन्होंने राजनीतिक फायदों के लिए अपनी ही संस्कृति पर शर्मिंदा होने की प्रवृत्ति स्थापित की। उन्होंने कहा कि कोई भी देश अपने अतीत को भूलकर एवं मिटाकर और अपनी ही जड़ों को काटकर प्रगति नहीं कर सकता।

प्रधानमंत्री असम में 11,600 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इन परियोजनाओं में पीएम-डिवाइन (प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फार नार्थ ईस्टर्न रीजन) के तहत मां कामाख्या दिव्य परियोजना भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा, मां कामाख्या के आशीर्वाद से उन्हें असम के लोगों के लिए इन परियोजनाओं को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। इन परियोजनाओं से असम व पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों की दक्षिण एशिया के अन्य देशों से कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इनसे पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा, 'अयोध्या में भव्य कार्यक्रम के बाद मैं अब मां कामाख्या के द्वार पर हूं। मुझे आज मां कामाख्या दिव्य परियोजना का शिलान्यास करने का मौका मिला। जब कोई कामाख्या मंदिर के दर्शन करता है तो उसे इस पवित्र स्थल की दिव्यता का अहसास होता है। जब यह परियोजना पूरी हो जाएगी तो यह देश और दुनियाभर के मां कामाख्या के भक्तों को अपार खुशी से भर देगी। पूरा होने पर यह पूरे पूर्वोत्तर के लिए पर्यटन का गेट-वे बन जाएगी। हजारों वर्षों की चुनौतियों के बावजूद तीर्थस्थल एवं मंदिर हमारी संस्कृति और हमारी दृढ़ता के प्रतीक हैं। इनमें से कई प्रतीक आजकल खंडहर बन गए हैं।' प्रधानमंत्री ने कहा, 'भाजपा विकास और विरासत की राजनीति कर रही है। एक तरफ हम अपने तीर्थों के उस गौरव को वापस लाए हैं जिसे पहले के शासनकाल में भुला दिया गया था, वहीं वर्तमान सरकार ने विकास को भी काफी महत्व दिया है।' उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकारों की इस नीति से युवाओं को काफी लाभ हुआ है। पिछले एक वर्ष में 8.5 करोड़ लोगों ने काशी, पांच करोड़ से ज्यादा ने महाकाल लोक और 19 लाख से ज्यादा ने केदारनाथ धाम की यात्रा की। प्राण प्रतिष्ठा के बाद सिर्फ 12 दिनों में 24 लाख से ज्यादा लोग अयोध्या पहुंच चुके हैं। इससे गरीब से गरीब लोगों की आमदनी में वृद्धि हुई है।

गुवाहाटी में रविवार को रोड शो के दौरान लोगों का अभिवादन करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। साथ में हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा। एपी >>

जीरो बिजली बिल की ओर बढ़ रहे

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार घरों का बिजली बिल जीरो करने की दिशा में काम कर रही है। कहा, 'हमने देश के हर घर में बिजली कनेक्शन देने का कार्यक्रम चलाया। बजट में हमने एक करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की योजना की घोषणा की है। इससे न केवल बिजली बिल जीरो हो जाएगा, बल्कि लोग अपने घरों में बिजली उत्पादन प्रणाली लगा सकेंगे। यहां तक कि वे पैसा कमाने के लिए अपने घरों की छतों पर लगे सोलर पैनल के जरिये उत्पादित बिजली को बेच भी सकते हैं।'

असम और पूर्वोत्तर का दक्षिण एशिया के बराबर विकास चाहते हैं युवा : पीएम पेज>>3

भारतीय दूतावास का कर्मी पाक के लिए जासूसी में गिरफ्तार

मास्को में तैनात रहे सतेंद्र पर देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का मुकदमा दर्ज

जागरण टीम, लखनऊ

मास्को स्थित भारतीय दूतावास में तैनात कर्मचारी सतेंद्र सिवाल को रविवार को यूपीएटीएस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ के लिए जासूसी करने के आरोप में मेरठ से गिरफ्तार कर लिया। हापुड़ के इस जासूस पर एटीएस लंबे समय से निगाह रख रही थी। वह विदेश मंत्रालय में मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के रूप में सुरक्षा सहायक के पद पर तैनात था और दो साल पहले डेपुटेशन पर मास्को भेजा गया था। उसके खिलाफ लखनऊ के एटीएस थाने में धारा 121ए (देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ना) और आफिशियल सीक्रेट एक्ट-1923 के तहत केस दर्ज किया गया है। शाम को लखनऊ में ही विशेष अदालत में पेश कर एटीएस ने उसे 14 दिन के रिमांड पर ले लिया। वहीं सूत्रों के अनुसार विदेश मंत्रालय को सिवाल की गिरफ्तारी की जानकारी है और अधिकारी लगातार जांच एजेंसियों के संपर्क में हैं।

अहम सूचनाएं पहुंचाता था पाक तक: एडीजी एटीएस मोहित अग्रवाल ने बताया कि सतेंद्र आइएसआइ के हैंडलर के रूप में काम कर रहा था। वह भारतीय दूतावास, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और भारतीय सैन्य संस्थानों की सूचनाएं आइएसआइ तक पहुंचा रहा था। इंटेलीजेंस व खुफिया विभाग की जांच में उसकी सच्चाई सामने आई। वह 2021 से डेपुटेशन पर मास्को के भारतीय दूतावास में तैनात था। इस बीच वह छुट्टी लेकर घर आया था। रविवार को एटीएस की टीम ने उसे मेरठ के गंगानगर स्थित कार्यालय बुलाया, जहां सारे साक्ष्य उसके सामने रखकर पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। एटीएस अधिकारियों के अनुसार मास्को पहुंचने के बाद से ही वह आइएसआइ के चंगुल में फंस गया था और और महत्वपूर्ण गोपनीय सूचनाएं व दस्तावेज उन तक पहुंचा रहा था। सेना की इंटेलीजेंस सूचना इकाई को यह जानकारी हुई तो उसने एटीएस से साझा की और आइएसआइ से संबद्धता के साक्ष्य भेजे। इसके बाद एटीएस ने इलेक्ट्रानिक सर्विलांस व अन्य माध्यमों से जांच शुरू की तो महत्वपूर्ण सुराग मिले। एटीएस प्रभारी राजीव त्यागी ने बताया कि सत्येंद्र के पास से दो मोबाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड व कुछ अन्य सामान बरामद किए गए हैं।

(देश सेवा भूल सतेंद्र बन गया पाकिस्तानी जासूस : पेज-6)

जासूसी के आरोप में गिरफ्तार भारतीय दूतावास कर्मी सत्येंद्र सिवाल। प्रेट्र

- सतेंद्र को यूपीएटीएस ने मेरठ से पकड़ा, छह माह से एजेंसियों की थी नजर
- मल्टी टास्किंग स्टाफ के रूप में सुरक्षा सहायक था आरोपित
- आइएसआइ के हैंडलर के रूप में कर रहा था काम
- विदेश मंत्रालय जांच एजेंसियों के संपर्क में, मामले पर रखी जा रही पैनी नजर

एटीएस व एसटीएफ की सक्रियता से कई जासूस गिरफ्तार

19 दिसंबर, 2018 को बीएसएफ जवान अच्युतानंद मिश्रा की नोएडा से गिरफ्तारी।

8 जनवरी, 2021 को हापुड़ निवासी सेना के पूर्व सैनिक सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी।

16 जुलाई, 2023 को गोंडा से मोहम्मद रईस की गिरफ्तारी।

23 जुलाई, 2023 को मुंबई से अरमान अली उर्फ सैयद व सलमान सिद्दीकी की गिरफ्तारी।

1 अगस्त, 2023 को गोंडा निवासी मुकीम सिद्दीकी की लखनऊ से गिरफ्तारी।

17 अगस्त, 2023 को कलीम गिरफ्तार। वह पाकिस्तान की जेल से छूटने के बाद मेरठ में पाक के लिए जासूसी कर रहा था।

26 सितंबर, 2023 को लखनऊ से शैलेंद्र कुमार पकड़ा गया।

21 नवंबर, 2023 को लखनऊ निवासी वसीउल्लाह पकड़ा गया।

26 नवंबर, 2023 को लखनऊ से रियाजुद्दीन व पंजाब के अमृतपाल गिल की गिरफ्तारी।

3 दिसंबर, 2023 को भारत नेपाल सीमा पर रुपईडीहा से चीन के ली जिन मेई की गिरफ्तारी

अन्य को फंसाने में करता था आइएसआइ की मदद

जांच में सामने आया है कि सतेंद्र दूतावास सहित मास्को में विभिन्न पदों पर तैनात भारतीय अधिकारियों व कर्मचारियों को फंसाने (हनी ट्रैप) के लिए आइएसआइ एजेंटों की मदद करता था। एटीएस की टीमें यह जानकारी जुटा रही हैं कि उसने कितनों को फंसाने में मदद की थी।

आइएसआइ से मिलती थी मोटी रकम, खातों को खंगाला जा रहा

सतेंद्र को आइएसआइ के एजेंटों से मोटी रकम भी मिलती थी। उसने कितनी गोपनीय सूचनाएं आइएसआइ को दी हैं इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। उसके बैंक खातों को भी खंगाला जा रहा है। साथ ही परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ की जा रही है कि वह हापुड़ में किन लोगों के साथ संपर्क में था।

तीन फार्मूलों पर काम कर रही है आइएसआइ

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (आइएसआइ) भारत में जाल फैलाने के लिए तीन फार्मूलों पर काम कर रही है। इनमें धर्म की दुहाई व हनी ट्रैप के अलावा लोगों को पैसों का लालच शामिल है। आइएसआइ के संपर्क में आए ज्यादातर जासूसों से पूछताछ में राजफाश हुआ है कि मुस्लिम समुदाय के युवाओं को धर्म के नाम पर भारत के विरुद्ध भड़काया जाता है। इसके बाद उनका ब्रेन वाश करके उनसे जासूसी करवाई जाती है। बदले में उन्हें पैसे भी दिए जाते हैं। जो लोग कट्टरता के जाल में नहीं फंसते हैं उन्हें पैसों का लालच दिया जाता है। अंतिम फार्मूला हनी ट्रैप का अपनाया जाता है।

कौशिक एकेडमी

उत्तराखंड में यूसीसी ड्राफ्ट पर कैबिनेट की मुहर

राज्य ब्यूरो, देहरादून

- **आज से शुरू हो रहा विधानसभा सत्र, मंगलवार को पेश किया जाएगा विधेयक**
- **कैबिनेट को दी गई संहिता के ड्राफ्ट में शामिल संस्तुतियों की विस्तृत जानकारी**

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही धामी सरकार ने विधानसभा में विधेयक पेश करने से पहले कैबिनेट के सदस्यों को इसके सभी पहलुओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में रविवार शाम हुई कैबिनेट की बैठक में समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट पर मुहर लगा दी गई। साथ ही, इससे संबंधित विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने का अनुमोदन भी किया गया। सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में मंगलवार को यह विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।

मुख्यमंत्री आवास में हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी व विशेष सचिव गृह रिद्धिम अग्रवाल ने समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट का प्रस्तुतिकरण दिया। बैठक का विषय

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सौजन्य : सूवि

समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट पर चर्चा और इसके विविध पहलुओं से कैबिनेट के सदस्यों को अवगत कराना था। विस सत्र आहूत होने के कारण कैबिनेट बैठक के संबंध में ब्रीफिंग नहीं की गई। लगभग 45 मिनट तक चली बैठक में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से मंत्रिमंडल के सदस्यों को ड्राफ्ट के चारों खंडों की विस्तृत जानकारी दी गई। सूत्रों के अनुसार प्रस्तुतिकरण के दौरान बताया गया कि राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के पीछे उद्देश्य क्या है। साथ ही ड्राफ्ट में महिला अधिकारों के संरक्षण के विषय में शामिल संस्तुतियों पर प्रकाश डाला गया। मंत्रिमंडल को अवगत कराया गया कि संहिता में केवल राज्य से संबंधित विषयों को ही लिया गया है। जिन विषयों पर केंद्र के स्तर से कानून बने हुए हैं, उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसमें सभी धर्मों के हितों को सुरक्षित रखा गया है। बताया गया कि प्रदेश की जनजातियों की अपनी विशिष्ट पहचान, संस्कृति और परंपराएं हैं। विशेष यह कि जनजातियों का विषय केंद्र के अधिकार क्षेत्र का है। इस कारण जनजातियों को संहिता के दायरे से बाहर रखा गया है।

समान नागरिक संहिता के प्रमुख बिंदु पेज>>3

कानून पालन के लिए भौगोलिक सीमा बाधा नहीं होनी चाहिए : अमित शाह

कहा, तीन नए कानूनों के अमल के बाद सबसे आधुनिक होगी भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने की अटार्नी एंड सालिसिटर जनरल कांफ्रेंस के समापन समारोह की अध्यक्षता

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कामनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन द्वारा आयोजित दो दिवसीय अटार्नी एंड सालिसिटर जनरल कांफ्रेंस के समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा पार की न्यायिक चुनौतियों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। कहा कि अपराध और व्यापार दोनों ही आज भौगोलिक सीमा को पार कर चुके हैं। अपराध को नियंत्रित करने और व्यापार को बढ़ाने के लिए सिर्फ राष्ट्रमंडल देशों को ही नहीं, बल्कि विश्व के सभी देशों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने जोर दिया कि अपराध और व्यापार के लिए सीमा को मर्यादा नहीं, मीटिंग प्वाइंट बनाना होगा।

विज्ञान भवन में आयोजित कांफ्रेंस में रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की मौजूदगी में उनकी ही बात को दोहराते हुए अमित शाह ने दावा किया कि पिछड़े क्षेत्र के आदिवासी वर्ग के व्यक्ति का राष्ट्रपति पद तक पहुंचना बताता है कि भारत में लोकतंत्र की भावना और संविधान की जड़ें कितनी गहरी हैं। राष्ट्रपति मुर्मु ने कांफ्रेंस के समापन समारोह की अध्यक्षता की। शाह ने आगे कहा कि यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है, जब भौगोलिक सीमा का विश्व में कोई महत्व नहीं रहा है। न व्यापार के लिए और न ही अपराध के लिए। हमें इससे निपटना है तो कोई न कोई नई व्यवस्था और परंपरा शुरू करनी होगी। गृह मंत्री ने वैश्विक न्यायिक चुनौतियों और संस्थागत पहुंच को सबसे प्रासंगिक और महत्वपूर्ण बताते हुए जोर दिया कि इस पर आगे भी काम होना चाहिए।

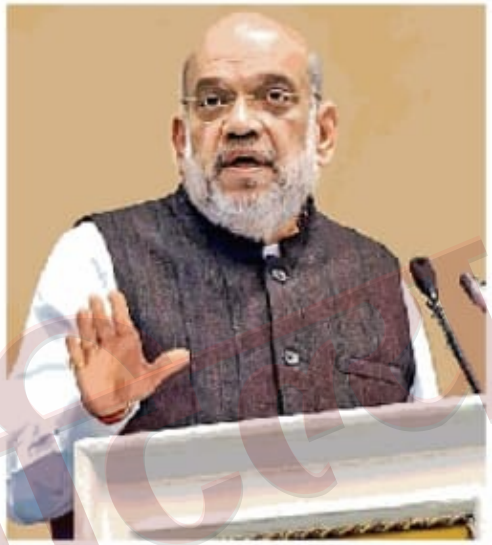

नई दिल्ली में रविवार को कामनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन द्वारा आयोजित अटर्नी एंड सालिसिटर जनरल कांफ्रेंस के समापन समारोह को संबोधित करते गृह मंत्री अमित शाह। प्रेट्र

गृह मंत्री ने कहा कि छोटे साइबर फ्राड से लेकर वैश्विक संगठित अपराध, स्थानीय सीमा विवाद से लेकर वैश्विक सीमा विवाद और स्थानीय अपराध से लेकर अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का जुड़ाव भी गहरा हो चुका है। आज अपराध और अपराधी, दोनों ही सीमा को नहीं मानते हैं। इनको नियंत्रित करने की दिशा में कानून के पालन के लिए कुछ आगे करना होगा, अन्यथा अपराध रोकने और व्यापार को बढ़ाने के लिए विश्व का वातावरण नहीं बना पाएंगे। भौगोलिक सीमा कानून के लिए मर्यादा नहीं होनी चाहिए, बल्कि मीटिंग प्वाइंट होना चाहिए। तभी हम मिलकर न्याय नीचे तक पहुंचा पाएंगे। हमें सहयोग और समन्वय को मूल मंत्र बनाना होगा। भारत की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए शाह ने राष्ट्रमंडल देशों के प्रतिनिधियों को बताया कि भारत ने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है। व्यापारिक विवाद और आपराधिक कानूनों के पूर्ण सुधार के लिए लंबी चर्चा के बाद इसका कलेवर और स्वरूप बदला है। तकनीक का उपयोग हर जगह इतना बढ़ाया है कि तकनीक में आने वाले सौ वर्ष में जितने भी बदलाव आएंगे, उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा। कहा कि आज बदले परिदृश्य के साथ न्याय पालिका को भी बदलना होगा। हम 19वीं सदी के कानून से 21वीं सदी में जस्टिस डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। भारत में बनाए गए तीन कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य कानून के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत विश्व में सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली बनेगा।

विकसित भारत की ओर

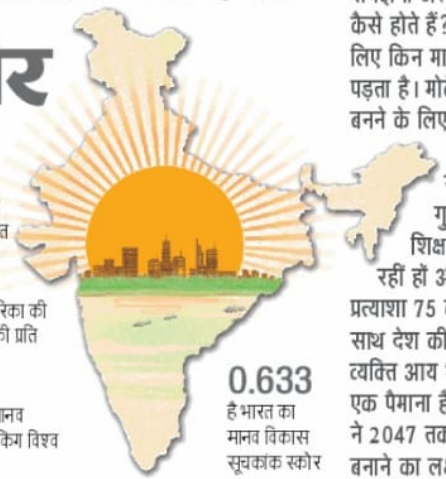

142 वें स्थान पर है भारत प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से दुनिया के 197 देशों में विश्व बैंक के अनुसार। भारत की प्रति व्यक्ति आय सालाना 2400 डालर है

76,000 डालर है अमेरिका की सालाना प्रति व्यक्ति आय, चीन की प्रति व्यक्ति आय है 12,700 डालर

132 वीं है संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग विश्व के 197 देशों में

0.633 है भारत का मानव विकास सूचकांक स्कोर

हर गरीब या विकासशील देश विकसित बनना चाहता है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि विकसित देश कैसे होते हैं? विकसित देश बनने के लिए किन मानकों पर खरा उतरना पड़ता है। मोटे तौर पर विकसित देश बनने के लिए जरूरी है कि देश के नागरिकों का जीवन स्तर अच्छा हो। उनको गुणवत्तपूर्ण स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं मिल रहीं हों और नागरिकों की जीवन प्रत्याशा 75 वर्ष से अधिक हो। इसके साथ देश की अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय भी विकसित देश के लिए एक पैमाना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य तय किया है। माना जा रहा है कि वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट के माध्यम से विकसित भारत को लेकर एक रूपरेखा देश के सामने रखी है। मोदी सरकार ने 10 वर्ष के कार्यकाल में वित्तीय समावेशन, बुनियादी जरूरतों और इन्फ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर देश को इस स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां से विकसित भारत की ओर एक बड़ी छलांग लगाई जा सकती है। हालांकि इस राह में अभी कई चुनौतियां भी हैं। भारत दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है लेकिन मानव विकास के तमाम संकेतकों में हम काफी पीछे हैं। ऐसे में यह पड़ताल अहम मुद्दा है कि अंतरिम बजट क्या विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम है?

टिकाऊ विकास के लिए जनसंख्या में स्थिरता जरूरी

विवेक देवराय
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष

आदित्य सिन्हा
पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद में अपर निजी सचिव (अनुसंधान)

तेजी से बढ़ रही आबादी एक चुनौती है। ये देश के टिकाऊ विकास पर असर डाल सकती है। विशेषाधिकार प्राप्त समिति तेज जनसंख्या वृद्धि के असर पर विचार के साथ जनसंख्या को स्थिर बनाने के लिए रणनीति बना सकती है। इससे विकसित भारत के एजेंडे पर काम करने में मदद मिलेगी।

वर्ष 2047 तक विकसित भारत या विकसित भारत की आवश्यकता प्रकृति के साथ संतुलन बनाते हुए एक समृद्ध राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की उपज है। विकसित देश में सभी नागरिकों के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा होगा और सबको समान अवसर मिलेंगे। विकसित भारत पर सरकार का फोकस बताता है कि टिकाऊ विकास, इन्फ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण और समावेशी विकास उसकी प्राथमिकता है। वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में इन्फ्रा के लिए पूंजीगत खर्च 11,11,111 करोड़ रुपये रखा है। इस मद में अप्रत्याशित इजाफा इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को बताता है। बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर न सिर्फ बेहतर कनेक्टिविटी और व्यापार की सुविधा देता है बल्कि ये आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को भी बेहतर बनाता है। ये नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को ऊपर उठाता है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और महिलाओं के लिए चलाई जा रही स्कीमों पर जोर दिया है। बजट भाषण में सशक्तीकरण, शिक्षा, तकनीक और नौकरियों का बार-बार उल्लेख किए जाने से भी यह साफ हो जाता है कि सरकार का फोकस किन चीजों पर है। बजट में सस्ते घर, स्वास्थ्य सुविधाओं, पूंजीगत खर्च के साथ एक बड़े फंड की घोषणा के साथ शोध एवं नवाचार पर भी जोर दिया गया है जो आर्थिक और सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए मजबूत नींव बनाने का काम करेगा। ये विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इसके अलावा तेजी से बढ़ रही आबादी की चुनौती का सामना करने के लिए अंतरिम बजट में विशेषाधिकार प्राप्त समिति बनाने की घोषणा की गई है। तेजी से बढ़ रही आबादी और जनसांख्यिकीय बदलाव देश के टिकाऊ विकास और देश की वित्तीय सेहत और सामाजिक प्रगति पर गहरा असर डाल सकता है।

भारत दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। बड़ी आबादी देश के आर्थिक विकास पर कई तरह से असर डालती है। तेजी से बढ़ती आबादी चुनौतियों को बढ़ाती है। पानी, जमीन, ऊर्जा और अन्य जरूरी संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। इससे इन संसाधनों के अत्यधिक दोहन के हालात बन सकते हैं और भविष्य की पीढ़ियों को इन संसाधनों की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। विशेषाधिकार प्राप्त समिति देश की जनसंख्या को स्थिरता की तरफ ले जाने के लिए रणनीति बना सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर लंबे समय से काफी अधिक रही है। यह राज्य लोगों तक स्वास्थ्य, शिक्षा और इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं पहुंचाने में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इसकी वजह संसाधनों पर दबाव है। वहीं दूसरी तरफ स्थिर जनसंख्या वृद्धि वाले प्रदेश जैसे केरल और तमिलनाडु अपेक्षाकृत कम आबादी और संसाधनों के बेहतर आवंटन की वजह से लोगों को जरूरी सुविधाएं पहुंचाने में ज्यादा सफल रहे हैं। तेजी से जनसंख्या बढ़ने से सेवाओं की डिलिवरी अलग अलग राज्यों पर अलग तरीके से असर डालती है। राज्यों का प्रशासन, आर्थिक विकास और सामाजिक नीतियों जैसे कारक इसे प्रभावित करते हैं। लेकिन कई अध्ययनों से यह बात साबित होती है कि छोटी आबादी वाले राज्यों के लिए बड़ी आबादी वाले राज्यों की तुलना में अपनी आबादी के एक बड़े हिस्से को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना अपेक्षाकृत आसान होता है। जिन राज्यों में जनसंख्या घनत्व काफी अधिक होता है उनके लिए अपने सभी नागरिकों को सुविधाएं मुहैया कराना और मुश्किल हो जाता है। ऐसे में विशेषाधिकार प्राप्त समिति जनसंख्या को स्थिर बनाने के लिए रणनीति बना सकती है।

तेजी से बढ़ती आबादी ने शहरीकरण को तेज किया है। इससे मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बढ़ा है और नए इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास की जरूरत पैदा हुई है। इसमें आवास, परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं शामिल हैं। कुछ शहरों में तेजी से आबादी बढ़ने की वजह से झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके तेजी से बढ़े हैं। इसके अलावा जनसंख्या तेजी से बढ़ने की वजह से स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव बढ़ सकता है और इससे हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना मुश्किल हो सकता है। इसकी वजह से माताओं और बच्चों की मृत्यु दर बढ़ सकती है। संक्रामक बीमारियां फैल सकती हैं। अच्छी बात यह है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बताता है कि भारत की जनसांख्यिकीय स्थिति में बड़ा बदलाव आ रहा है और प्रजनन दर घटकर 2 बच्चे प्रति महिला पर आ गई है। 2015-16 के सर्वे में प्रजनन दर 2.2 थी। इस गिरावट से पता चलता है कि हम उस स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं जहां जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। यानी जनसंख्या बढ़ेगी नहीं। जितने लोगों की मौत होगी, लगभग उतनी ही संख्या में बच्चों का जन्म होगा। प्रजनन दर में गिरावट श्रम शक्ति की संख्या को भी प्रभावित करेगी। इसके अलावा बुजुर्गों की आबादी बढ़ने से उनकी देखभाल के लिए संसाधनों और बेहतर नीतियों की जरूरत होगी।

विशेषाधिकार प्राप्त समिति की घोषणा को इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। कुछ राज्यों में जनसंख्या स्थिर हो चुकी है लेकिन सभी राज्यों में ऐसा नहीं हुआ है। विशेषाधिकार प्राप्त समिति इस बात पर विचार कर सकती है कि बढ़ती आबादी राज्यों के टिकाऊ विकास को कैसे प्रभावित कर सकती है और ग्रोथ को कैसे बाधित कर सकती है। इससे सरकार को बढ़ती आबादी की समस्या से निपटने के लिए नीतियां बनाने में मदद मिलेगी और सरकार विकसित भारत के एजेंडे पर काम कर सकेगी।

विकसित देश के लिए क्या हैं पैमाने

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हुए कहा था कि 2047 तक भारत एक विकसित देश होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि उनके तीसरे कार्यकाल में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश होगा। भारत अभी दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन विकसित देश कैसा होता है आइये समझते हैं।

विकसित देश के लिए परिपक्व अर्थव्यवस्था जरूरी

एक विकसित देश की अर्थव्यवस्था आमतौर पर परिपक्व और परिष्कृत होती है। हो सकता है कि उनकी अर्थव्यवस्था वर्तमान समय में बहुत तेज गति से न बढ़ रही हो लेकिन बीते दौर में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर जरूर काफी अधिक रही होगी। विकसित देशों में उन्नत तकनीकी इन्फ्रास्ट्रक्चर, मजबूत औद्योगिक ढांचा और सेवा क्षेत्र होता है। उनके नागरिकों को गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है और उच्च शिक्षा तक पहुंच आसान होती है।

किसी देश को 'विकसित' कैसे माना जाता है?

कोई देश विकसित है या नहीं, यह तय करने के लिए कई कारकों पर विचार किया जाता है। जैसे आर्थिक कारक। इसमें प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिकीकरण का स्तर, नागरिकों के रहन सहन का स्तर और तकनीकी इन्फ्रा शामिल है। गैर आर्थिक कारकों में मानव विकास सूचकांक शामिल है। मानव विकास सूचकांक में शिक्षा, स्वास्थ्य और साक्षरता जैसे कई मानक शामिल है।

मानव विकास सूचकांक

संयुक्त राष्ट्र का मानव विकास सूचकांक (एचडीआइ) देशों की तीन मानकों पर रैंकिंग करता है। ये तीन मानक हैं साक्षरता दर, शिक्षा तक पहुंच और स्वास्थ्य सुविधाएं। सभी देशों को इन तीन मानकों के आधार 0 से 1 के बीच अंक दिए जाते हैं। 0.8 से अधिक एचडीआइ स्कोर वाले देश को आमतौर पर विकसित देश माना जाता है। वर्तमान में भारत का एचडीआइ स्कोर 0.633 है और भारत की रैंकिंग 192 देशों में 132वीं है।

प्रति व्यक्ति आय

एक अर्थव्यवस्था में विकास का स्तर तय करने के लिए प्रमुख मापदंड प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्त आय आम तौर पर देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को कुल आबादी से भाग करके निकाली जाती है। यह मोटे तौर पर बताती है कि एक देश के नागरिक की सालाना आय कितनी है। कुछ अर्थशास्त्री विकसित देशों के लिए 12,000 से 15,000 डालर प्रति व्यक्ति आय काफी मानते है। वहीं, कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि एक विकसित देश की प्रति व्यक्ति आय 25,000 डालर या 30,000 डालर से अधिक होनी चाहिए। विश्व बैंक के अनुसार, भारत की प्रति व्यक्ति आय करीब 2,400 डालर है। वहीं अमेरिका और चीन की प्रति व्यक्ति आय क्रमशः 76,400 डालर और 12,700 डालर है।

रहन सहन का स्तर और दूसरे पैमाने

जिन देशों के लिए प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विकसित देश की श्रेणी में रखना मुश्किल है, उनके लिए अर्थशास्त्री जीवन स्तर को पैमाना बनाते हैं। ज्यादातर विकसित देशों में 1,000 जीवित बच्चों के जन्म पर 10 से कम मौतें होती हैं। इसके अलावा इन देशों में जीवन प्रत्याशा 75 वर्ष से अधिक है। ऐसा एक उदाहरण कतर है। कतर की प्रतिव्यक्ति आय दुनिया में काफी अधिक 88,000 डालर है। लेकिन आय में अत्यधिक असमानता और शिक्षा के मौके कम होने के कारण इसे विकसित देशों में नहीं गिना जाता है।

तेज आर्थिक विकास से पूरा होगा सपना

भारत को 2047 तक विकसित देश बनने के लिए अगले 20 वर्षों में आर्थिक विकास की दर 8-9 प्रतिशत रखनी होगी। डेलाइट दक्षिण एशिया के सीईओ रोमल शेट्टी का कहना है कि भारत में क्षमता है कि वह आर्थिक विकास की इस दर को हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि 2047 तक हम एक विकसित देश होंगे और हमारी अर्थव्यवस्था ज्यादा समावेशी होगी।

महिला सशक्तीकरण को समर्पित सरकार

स्मृति इरानी

आज महिला-प्रधान विकास केवल कुछ कार्यक्रमों तक सीमित नहीं, बल्कि राष्ट्र की विकास गाथा के केंद्र में खड़ा है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज एक समावेशी राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, जिसमें लैंगिक समानता को महत्व दिया जा रहा है। महिलाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रभावी नीतियां अपनाकर भारत की विकास गाथा में एक नया आयाम जोड़ा जा रहा है। पूर्व में लैंगिक समानता के मोर्चे पर निराशा की स्थिति थी, लेकिन आज उसकी जगह लोकतांत्रिक नीतियों और उनके सफल कार्यान्वयन ने ले ली है। आज शासन-प्रशासन के ढांचे में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और उनका कार्यालय कठिनाई से अर्जित इस संप्रभुता का प्रतीक है। उनकी आदिवासी पहचान राष्ट्रपति के पद को और भी गौरवशाली बनाती है। अंतरिम बजट में उनकी अध्यक्षता एक अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण रहा। यह ऐतिहासिक क्षण 75वें गणतंत्र दिवस के साथ मेल खाता है, जो समानता और न्याय के सिद्धांतों को मूर्त रूप देता है। 75 वर्षों के बाद भाजपा सरकार में महिलाओं को जल, थल, नभ और अंतरिक्ष सहित सभी क्षेत्रों के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होते देखा जा रहा है। इक्कीसवीं सदी महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किए गए विचारशील सुधारों का पड़ाव है। महिलाओं के जीवन में भाजपा सरकार में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं। जैसे 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण, 30.64 करोड़ मुद्रा लोन के वितरण और उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे वाली 10.1 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन उपलब्ध होना है। प्रजनन अधिकारों पर भी अब खुलकर चर्चा हो रही है। हालिया बजट घोषणाओं के अनुसार 36 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया गया है। यह सभी सामाजिक वर्गों की महिलाओं के प्रति मोदी जी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

यह दृष्टिकोण भारतीय महिलाओं की व्यावसायिक क्षमता का उपयोग करके तीन करोड़ महिलाओं को उद्यमी बनाने पर केंद्रित है। इन उद्यमियों को 'लखपति दीदी' के रूप में जाना जाएगा। इन महिलाओं के प्रति वर्ष एक लाख रुपये या उससे अधिक की आय अर्जित करने की उम्मीद है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को बदलने के लिए, ''ड्रोन दीदी'' योजना से कृषि के तौर-तरीके आधुनिक होंगे और पैदावार भी बढ़ेगी। महिलाओं के लिए ऐसी पहल 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने और प्रधान सेवक के तौर पर देश की सेवा पर जोर देने से हुई। महिलाओं के लिए विधायिका में 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना और अनुच्छेद 370 को समाप्त करना क्रमशः महिलाओं की समान भागीदारी को बढ़ावा देने और संपूर्ण राष्ट्र को एकजुट करने की ओर प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

अवधेश राजपूत

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिंग-समावेशी निधि को शामिल करना प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता को दर्शाता है। यह निधि बालिकाओं की शिक्षा और कल्याण के लिए निरंतर हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है। 15वें वित्त आयोग ने भी अंतर-सरकारी राजकोषीय हस्तांतरण फार्मूले में लैंगिक पहलू को शामिल किया है, जिससे भारत में लैंगिक न्याय के लिए एक मजबूत आधार बना है। इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में बड़ी संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं। अनुसंधान एवं नवाचार में एक लाख करोड़ का निवेश दिखाता है कि आज का भारत तेजी से विकास की नई बुलंदियों पर स्वयं को स्थापित कर रहा है। उल्लेखनीय है कि सभी एसटीईएम (साइंस, टेक, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स) स्नातकों में 43 प्रतिशत महिलाएं हैं, जो कई विकसित देशों से कहीं आगे हैं।

भारत सरकार ने 2024-25 के बजट में महिलाओं के विकास और कल्याण पर खर्च को पिछले साल के मुकाबले 38.7 प्रतिशत बढ़ा दिया है। जेंडर बजट स्टेटमेंट के अनुसार 2024-25 में 43 मंत्रालयों/विभागों/केंद्र शासित प्रदेशों को 2023-24 की तुलना में आवंटन 38.6 प्रतिशत अधिक बढ़ा है। इसके परिणामस्वरूप कुल केंद्रीय बजट में लैंगिक बजट का हिस्सा पांच प्रतिशत से बढ़कर 6.5 प्रतिशत हो गया है। यह प्रतिबद्धता केवल घरेलू क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे जी-20 अध्यक्षता के दौरान नई दिल्ली घोषणा जैसी नीतियों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आगे बढ़ाया गया है। कोविड काल की विषम परिस्थितियों के दौरान जिस समय शीर्ष पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई थीं, तब भी भारतीयअर्थव्यवस्था मजबूत बनी रही। जी-20 का नई दिल्ली घोषणापत्र आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण, लैंगिक डिजिटल विभाजन को पाटने, लैंगिक-समावेशी जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने और महिलाओं की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। यह वैश्विक लैंगिक समानता के लिए भारत के समर्पण का प्रमाण है। विश्व आर्थिक मंच पर भारत की प्रभावशाली उपस्थिति इसे लैंगिक सशक्तीकरण के एक मजबूत समर्थक के रूप में प्रतिबिंबित करती है।

नीति-निर्माण में महिलाओं को परंपरागत रूप से सूक्ष्म आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री के दूरदर्शी दृष्टिकोण ने इस दिशा में व्यापक आर्थिक प्रभाव डाला है। स्वास्थ्य, शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लैंगिक समानता को न केवल स्वीकार किया गया है, बल्कि इसे शासन ढांचे में भी संबोधित किया गया है। मोदी जी ने महिलाओं को जिम्मेदारियां सौंपकर इस दृष्टिकोण पर काम किया है और विभिन्न क्षेत्रों में सार्थक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और सामाजिक स्तर के निचले पायदान पर महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। आज महिला-प्रधान विकास केवल कुछ कार्यक्रमों तक सीमित नहीं, बल्कि राष्ट्र की विकास गाथा के केंद्र में खड़ा है।

महिलाओं के नेतृत्व में विकास केवल जटिल योजनाओं तक सीमित न होकर राष्ट्र की प्रगति गाथा की नींव रखने वाला है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पहल को सफल बनाना और महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित किया जाना दर्शाता है कि प्रधानमंत्री के न्यू इंडिया विजन में नारी शक्ति की उपस्थिति को अभूतपूर्व महत्व दिया जा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में लैंगिक न्याय की ओर उठाए जा रहे कदम राष्ट्र को ऐसे युग की ओर ले जा रहे हैं, जहां मात्र खोखले राजनीतिक प्रलोभन नहीं, बल्कि प्रभावी कार्रवाई के लिए कदम उठाए जाते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश समावेशी विकास के साथ प्रगति के नए आयाम गढ़ रहा है।

(लेखिका केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं)

response@jagran.com

युवा और लोकतंत्र है ताकत

देश की आबादी में बड़ा हिस्सा युवाओं का है। ये आर्थिक विकास के मोर्चे पर भारत को एक बड़ी बढ़त दे रहा है। ऐसे में युवा आबादी और जीवंत लोकतंत्र विकसित भारत के लिए एक मंच मुहैया कराते हैं। इनके दम पर भारत अगले 25 वर्षों में खुद को एक विकसित देश बना सकता है।

विकास सिंह
मैनेजमेंट गुरु और वित्तीय एवं समग्र विकास के विशेषज्ञ

भारत वर्तमान समय में तेज बदलाव से गुजर रहा है और अगले 25 वर्षों में विकसित अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। सामाजिक-आर्थिक बदलाव की भारत की यह यात्रा मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर, तेज आर्थिक विकास, उद्यमिता, ढांचागत सुधारों के साथ आगे बढ़ी है। टिकाऊ विकास, सबको समान अवसर और संसाधनों का समुचित बंटवारा इस विकास यात्रा की विशेषता हैं। 140 करोड़ की आबादी में युवाओं की बड़ी हिस्सेदारी और जीवंत लोकतंत्र भारत के तेज आर्थिक विकास को एक मजबूत मंच दे रहे हैं। बीते वर्षों में भारत में ताकतवर डिजिटल क्रांति का उभार देखा गया है। भारत ने शानदार तरीके से अपनी संस्थागत क्षमता को बनाया और बढ़ाया है। नवाचार संस्थान जैसे यूआइडीएआइ, इसरो, आरबीआइ, सेबी, नाबार्ड, चुनाव आयोग, जीएसटीआइएन देश के आर्थिक परिदृश्य को आकार देने और रचनात्मकता व नवाचार के जरिए जटिल चुनौतियों का समाधान करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। एक स्थिर लोकतंत्र निवेशकों का भरोसा मजबूत करता है लेकिन लंबी अवधि की स्थिरता के लिए लोकलुभावन राजनीति और राजनीतिक ध्रुवीकरण पर अंकुश लगाना अहम हो जाता है। स्मार्ट सिटी और समर्पित माल ढुलाई गलियारे जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देश को जोड़ते हैं। लेकिन इन प्रोजेक्ट के लिए संसाधन जुटाना और इनका क्रियान्वयन एक चुनौती है। नए विचारों और तरीकों से इस चुनौती का समाधान किया जा सकता है। राजनीतिक परिदृश्य में स्थिरता नीतियों में निरंतरता सुनिश्चित करती है लेकिन तरक्की अबाध गति से जारी रहे, इसके लिए नौकरशाही से जुड़ी बाधाओं को दूर करने की जरूरत है। क्षेत्रीय विकास और रोजगार पैदा करने में बेहद अहम भूमिका निभाने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए वित्त और तकनीक हासिल करना अब भी एक मुश्किल काम है। लंबे समय से चुनौती बनी प्रतिभा पलायन की समस्या को रोकने की पहल और प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजी गई रकम के प्रभावी उपयोग से दूर किया जा सकता है। बालीवुड, योग और आयुर्वेद के माध्यम से सांस्कृतिक व्यवहार विदेशों में भारत की जीवंत छवि को प्रदर्शित करता है। महत्वपूर्ण देशों के साथ रणनीतिक साझेदारियां व्यापार, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करती हैं। ये भारत की स्थिर साझेदारी की स्थिति को मजबूत करतीं हैं। आइटी, विनिर्माण और स्वास्थ्य सेक्टर में वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने की असीम संभावनाएं हैं। अनुसंधान और विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो सुनिश्चित करती हैं कि भारत तकनीकी नवाचार की दौड़ में आगे रहे।

भारत ने डिजिटल क्षेत्र में एक मजबूत तकनीकी इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। इसने न सिर्फ कारोबार और लेनदेन को और आसान बनाया है बल्कि इससे डिजिटल डोमेन में वैश्विक स्तर पर भारत का कद बढ़ा है। तकनीकी बदलाव के साथ-साथ डिजिटल इंडिया जैसी सरकारी पहलों ने भारत को डिजिटल क्षेत्र में एक अग्रणी ताकत के तौर पर स्थापित किया है, जो आगे और तरक्की व वैश्विक स्तर पर भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करता है।

भारत के बदलाव की यात्रा को डिजिटल पुनर्जागरण का समर्थन मिल रहा है, जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता और पारदर्शिता को बढ़ावा दे रहा है। भारत की विनिर्माण क्षमता रणनीतिक स्तंभों पर टिकी हुई है। इसके तहत कारोबारी परिचालन को सरल बनाने, इन्फ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने, अबाध लाजिस्टिक्स सुनिश्चित करने और वित्त की उपलब्धता आसान बनाने पर जोर दिया जा रहा है। पीएलआइ, कौशल विकास जैसी पहलों और तकनीक के इस्तेमाल ने भारत के विनिर्माण क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया है। इलेक्ट्रानिक्स, आटोमोबाइल और फार्मास्युटिकल जैसे सेक्टर में उत्पादन को प्रोत्साहन देकर पीएलआइ ने न सिर्फ विनिर्माण की लागत को कम किया है बल्कि ये घरेलू और विदेशी निवेशकों को भी आकर्षित कर रहा है।

भारत की 140 करोड़ से अधिक आबादी में एक बड़ा हिस्सा युवाओं का है, जो भारत को आर्थिक विकास के मोर्चे पर बढ़त देता है। युवा श्रम शक्ति न सिर्फ अपने कौशल और श्रम के जरिए अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देते हैं बल्कि आय बढ़ने के साथ युवा खपत को बढ़ाने की क्षमता भी रखते हैं। युवाओं की यह दोहरी क्षमता भारत को एक मजबूत बाजार के तौर पर स्थापित करती है और एक व्यापक और विविधता से भरे उपभोक्ता आधार के साथ घरेलू और इंटरनेशनल ब्रांड को आकर्षित कर रही है। हालांकि, जनसांख्यिकीय लाभ की संभावनाओं का समुचित दोहन करने के लिए कौशल विकास और इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से युवाओं को प्रशिक्षित करने की जरूरत है। इसके अलावा श्रम शक्ति भागीदारी में लैंगिक असमानता को भी कम करना होगा। इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास ग्रामीण और शहरी इलाकों को जोड़ने का काम करता है। इस पर सरकार पहले से ही तेज गति से काम कर रही है। हालांकि वित्त की उपलब्धता, प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन और लाभ के समान वितरण को लेकर चुनौतियां बनी हुई हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देकर, नए वित्तीय माडल को अपनाकर और निगरानी व मूल्यांकन के मजबूत फ्रेमवर्क को लागू करके काम में तेजी लाई जा सकती है और प्रभावी इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। हालांकि भारत को विकसित देश बनाने की राह में चुनौतियां बनी हुई हैं। गरीबी और असमानता दूर करने के लिए बहुआयामी तरीके से काम करने की जरूरत है। योजनाओं के फायदे लोगों तक पहुंचाने के लिए डिलिवरी तंत्र को मजबूत करके, गरीबी कम करने के लक्षित कार्यक्रम चला कर और इसके असर का कठोरता से मूल्यांकन करके ही सबको विकास का लाभ दिया जा सकता है। इसके अलावा हर एक नागरिक के सशक्तीकरण के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और निवेश बढ़ाने की जरूरत है। तभी हम हर एक नागरिक को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं कम खर्च में उपलब्ध करा सकते हैं।

कौशिक अकादमी

विवेक ओझा
अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार

लाल सागर

क्षेत्रीय राजनीति का हथियार हाउती लड़ाके

लाल सागर में हाउती लड़ाकों का व्यापारिक समुद्री जहाजों पर हमला महज जहाज लूटने और उसे नष्ट करने तक सीमित नहीं है। यह पश्चिम एशिया की क्षेत्रीय राजनीति को हवा देने का जरिया बन गया है। इजरायल के फलस्तीन, ईरान, सीरिया, जार्डन, मिस्र से रिश्ते कैसे हैं और कैसे होने चाहिए, हाउती ने अपने हमलों से इसे चर्चा का विषय बना दिया है। ऐसे में अमेरिकी गुट, इजरायल और अन्य सहयोगी देशों की यह जिम्मेदारी है कि कूटनीति के जरिये यह सुनिश्चित हो कि कोई भी पक्ष गैर-जिम्मेदाराना कार्य न करे

वैश्विक तेल व्यापार का 12 प्रतिशत हिस्सा लाल सागर के जरिये होता है, इसलिए हाउती इन जहाजों को अधिक निशाना बनाते हैं। फाइल

जर्मनी के प्रसिद्ध सैन्य सिद्धांतकार कार्ल वान क्लाटविट्ज ने ठीक ही कहा था कि राजनीति वह गर्भाशय है जिसमें युद्ध विकसित होता है। लाल सागर में हाउती और पश्चिमी ताकतों के बीच छिड़ी जंग में यह बात बहुत हद तक सही दिखती है। अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिम एशिया की राजनीति को अपने चश्मे से देखते हैं, वहीं यहां की कुछ क्षेत्रीय शक्तियां पश्चिमी ताकतों खासकर अमेरिका और इजरायल के संदर्भ में 'प्रतिशोध और प्रतिरोध' का कठोर नजरिया रखती हैं। इसी रस्साकसी में सबसे गरीब अरब देश यमन के हाउती लड़ाकों ने लाल सागर क्षेत्र में गंभीर अस्थिरता उत्पन्न कर दी है। अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने सहयोगियों सहित हाउती ठिकानों पर मिलिट्री स्ट्राइक किए हैं। उत्तरी यमन के 13 जगहों पर 36 हाउती ठिकानों पर अमेरिका और ब्रिटेन का ये हमला सिद्ध करता है कि समुद्री व्यापार को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों और इजरायल को सबक सिखाने के सोच से काम करने वाली ताकतों को मुंहतोड़ जबाव दिया जाएगा।

अमेरिका और ब्रिटेन ने कुछ ही दिनों पहले ईरान और सीरिया में सात स्थानों पर 85 हाउती ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं और साफ कर दिया है कि ईरान और सीरिया की धरती पर हाउती लड़ाकों का मनोबल नहीं बढ़ने दिया जाएगा। ईरान और सीरिया यदि हाउती लड़ाकों को अपनी धरती पर सहयोग या समर्थन देते हैं तो उन्हें भी इसके परिणाम के लिए तैयार रहना होगा। अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा हाउती के विरुद्ध किए गए ताजा हमले में आस्ट्रेलिया, बहरीन, डेनमार्क, कनाडा, नीदरलैंड्स और न्यूजीलैंड ने अपना सहयोग दिया है। इन देशों ने खुफिया जानकारी और लाजिस्टिक्स के मामले में सहयोग किए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में महाशक्तियों, ईरान, लेबनान जैसी क्षेत्रीय ताकतों और खासकर हाउती लड़ाकों को यह समझना जरूरी है कि इजरायल के द्वारा हमास और गाजापट्टी के खिलाफ कार्रवाई का जो जवाब लाल सागर में दिया जा रहा है, वह सही तरीका नहीं है और वह ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के विरुद्ध कार्रवाई के रूप में माना जा रहा है। इससे शक्ति ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिलेगा। दो देशों के बीच शत्रुता के चलते होने वाला युद्ध थोड़े ही समय में वैश्विक राजनीति को नए मोड़ देने लगता है।

भारत के रक्षा मंत्रालय का निर्णय : मालवाहक जहाजों पर होने वाले हमले को रोकने और समुद्री लुटेरों पर लगाम को लेकर भारत सरकार ने भी बड़ा निर्णय लिया है। रक्षा मंत्रालय ने जिबूती से लेकर अदन की खाड़ी और सोमालिया तक भारतीय नौसेना की तैनाती का प्लान बनाया है। रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। इसमें मालवाहक जहाजों के संरक्षण के लिए भारतीय नौसेना की यूनिट्स को जिबूती, अदन की खाड़ी, सोमालिया के पूर्वी तट के साथ ही उत्तर और मध्य अरब सागर में भी तैनात किया जा रहा है। नौसेना हमलों में शामिल सूत्रों और भागीदारों की पहचान करने के लिए सहयोगी देशों के साथ सूचना साझा कर रही है। नौसेना ने अदन की खाड़ी और अफ्रीका के पूर्वी तटीय क्षेत्र में जलदस्यु रोधी गश्ती के लिए 2008 से अपनी यूनिट्स को तैनात किया था। कुल 3,440 जहाजों और 25 हजार से अधिक नाविकों को सुरक्षा प्रदान की गई है। भारत पहले भी अदन की खाड़ी में पीआइ-8 सर्विलांस एयरक्राफ्ट तैनात कर चुका है। भारत का प्राथमिक उद्देश्य समुद्री डकैती (पायरेसी) और वाणिज्यिक समुद्री जहाजों पर होने वाले ईरान समर्थित हाउती के हमलों को रोकना है। इसके लिए भारत को कूटनीतिक स्तर पर ईरान को साथ रखना करना होगा। ईरान के आर्थिक लाभ भारत से जुड़े हैं, दोनों चाबहार पोर्ट जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना से जुड़े हैं। दोनों ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य रहे हैं। हालांकि ये बातें सैद्धांतिक लग सकती हैं, लेकिन जब भी कोई क्षेत्रीय संघर्ष समाधान करना होता है तो हर प्रकार के रास्तों को तलाश करना होता है और उनकी अपनी संभावनाएं होती हैं।

हाउती का उद्देश्य : हाउती यमन के अल्पसंख्यक शिया 'जैदी' समुदाय का एक हथियारबंद समूह है। पिछली सदी के अंतिम दशक में तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्लाह सालेह के भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए इस समूह का गठन किया था। उनका नाम उनके अभियान के संस्थापक हुसैन अल हूती के नाम पर पड़ा है। वे स्वयं को 'अंसार अल्लाह' यानी ईश्वर के साथी भी कहते हैं। वर्ष 2003 में अमेरिका के नेतृत्व में इराक पर हुए हमले में हाउती विद्रोहियों ने नारा दिया था, ईश्वर महान है, अमेरिका का खात्मा हो, इजरायल का खात्मा हो, यहूदियों का विनाश हो और इस्लाम की विजय हो। हाउती स्वयं को हमास और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजरायल, अमेरिका और पश्चिमी देशों के विरुद्ध ईरान के नेतृत्व वाली 'प्रतिरोध की धुरी' का हिस्सा बताया था। हाउती विद्रोही लेबनान के सशस्त्र शिया समूह हिजबुल्लाह के माडल से प्रेरणा लेते हैं। अमेरिका के रिसर्च इंस्टीट्यूट 'कांबैटिंग टेररिज्म सेंटर' के अनुसार, हिजबुल्लाह ही उन्हें 2014 से बड़े पैमाने पर सैन्य विशेषज्ञता और ट्रेनिंग दे रहा है। हाउती स्वयं को ईरान का सहयोगी भी बताते हैं, क्योंकि उनका साझा दुश्मन है सऊदी अरब। हाउती उत्तरी यमन में सऊदी अरब द्वारा सुन्नी इस्लाम की सलाफी विचारधारा के विस्तार के विरोध में हैं। यमन के सलाफियों का सऊदी अरब से मजबूत लिंक रहा है। हाउती शिया हमेशा सऊदी अरब के इस आयाम से शंका से भरे रहे हैं कि सऊदी सत्ता परिवर्तन में भी राजनीति कर सकता है। हाउती जैदी शिया मुस्लिम जो देश की आबादी का 35 प्रतिशत हैं, अपने देश में सऊदी अरब के सलाफी प्रभुत्व और अत्याचार की आशंकाओं के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं और इसीलिए हाउती आंदोलन पिछली सदी के अंतिम दशक में एक कल्चरल रिवाइवलिस्ट आंदोलन के रूप में धार्मिक शुद्धता के लिए उभरा था।

कालांतर में हाउती को ईरान का साथ मिला। ईरान पर यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि हाउती विद्रोहियों को ईरान हथियार भी दे रहा है। यमन की अधिक आबादी हाउती विद्रोहियों के नियंत्रण में रहती है। उनका संगठन देश के उत्तरी हिस्से में टैक्स वसूलता है और अपनी मुद्रा भी छापता है। अमेरिका और सऊदी अरब कहते हैं कि ईरान ने हाउती विद्रोहियों को बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस किया था, जिनका उपयोग 2017 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर हमले के लिए किया गया था। इन मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया था। सऊदी अरब ने ईरान पर हाउती विद्रोहियों को क्रूज मिसाइल और ड्रोन देने का भी आरोप लगाया है।

हाउती विद्रोही सऊदी अरब पर कम रेंज वाली हजारों मिसाइल दाग चुके हैं और उन्होंने यूएई को भी निशाना बनाया है। इस तरह के हथियारों की सप्लाई करने का अर्थ है संयुक्त राष्ट्र की ओर से हथियारों पर लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करना, लेकिन ईरान इन सभी आरोपों को खारिज करता है। अपनी शक्तियों के दम पर हाउती विद्रोही लाल सागर के बड़े हिस्से को नियंत्रित करते हैं। यहां जहाजों को निशाना बनाना आसान होता है। दुनिया भर के तेल व्यापार का 12 प्रतिशत हिस्सा लाल सागर के जरिये ही आता-जाता है, इसलिए हाउती विद्रोही इन जहाजों को ज्यादा निशाना बनाते हैं। इसके जरिये वे पूरी दुनिया और खासकर सऊदी अरब पर दबाव बनाना चाहते हैं, क्योंकि यमन की सरकार वहीं से चलती है। हाउती विद्रोही, सऊदी अरब से और छूट चाहते हैं। हमलों के जरिये वे यह जताना चाहते हैं कि वे कभी भी लाल सागर के रास्ते को बंद कर सकते हैं। ऐसा करने से तेल के कारोबार में रुकावट आएगी और दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ेंगे, जिस कारण सऊदी अरब पर और दबाव आएगा। वहीं, इजराइल के जहाजों को इसलिए निशाना बनाते हैं, क्योंकि हाउती स्वयं को हमास का समर्थक बताते हैं। ऐसे में इजरायल और हमास के बीच जारी जंग के दौरान वे अपनी दोस्ती भी दर्शाना चाहते हैं।

भारतीय नौसेना की बढ़ती धमक

योगेश कुमार गोयल

भारतीय नौसेना में एक और बाहुबली योद्धा शामिल हो गया, जिसके बाद भारत की नौसैनिक ताकत और बढ़ गई है। भारतीय नौसेना के पहले सर्विलांस जहाज आइएनएस संधायक को समुद्र में भारत का 'गूगल मैप' बताया गया है। भारत का यह सर्वेक्षण जहाज समुद्र में भारतीय नौसेना की यात्रा को आसान तथा और ज्यादा आरामदायक बनाने में भूमिका निभाएगा व समुद्र में गूगल मैप की भांति कार्य भी करेगा। आइएनएस संधायक भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और तकनीकी प्रगति का प्रतीक है। इसे अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया गया है, जो इसे उपयोगी बनाते हैं। इसमें लगाए मल्टी-बीम इको-साउंडर्स समुद्र तल की गहराई का सटीक चित्रण प्रदान करते हैं, जबकि उपग्रह-आधारित पोजीशनिंग सिस्टम जहाज की सटीक स्थिति निर्धारित करते हैं। साइड स्कैन सोनार समुद्र तल की सतह और नीचे की वस्तुओं का पता लगाते हैं।

आइएनएस संधायक आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती जहाज निर्माण क्षमता का एक वास्तविक प्रमाण है। समुद्री क्षेत्रों की निगरानी करने और खतरों का पता लगाने में यह भूमिका निभाएगा, जिससे समुद्री सुरक्षा मजबूत होगी। चीन तथा अन्य क्षेत्रीय देशों के बढ़ते समुद्री दबाव का सामना करने और हिंद महासागर में भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ने हाल के वर्षों में अपनी नौसेना के बेड़े में कई नए युद्धपोत, सबमरीन, विमान इत्यादि शामिल किए हैं, जिनमें विमानवाहक पोत आइएनएस विक्रांत, स्वदेशी पनडुब्बियां, उन्नत मिसाइल विध्वंसक और फ्रिगेट्स शामिल हैं। नौसेना के बेड़े में इनकी उपस्थिति से भारतीय नौसेना की ताकत और क्षमताओं में काफी वृद्धि हुई है और भारतीय नौसेना हिंद महासागर में अब एक शक्तिशाली और सक्षम बल है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

सर्विकल कैंसर का बढ़ता खतरा

सोनम लववंशी

बीते दिनों बालीवुड एक्ट्रेस और माडल पूनम पांडे ने सर्विकल कैंसर पर अपनी मौत की झूठी खबर फैलाकर सनसनी फैला दी। पूनम पांडे का कृत्य निंदनीय है। निश्चित रूप से यह कैंसर पीड़ितों का अपमान है। सर्विकल कैंसर देश की महिलाओं के लिए गंभीर समस्या है। इससे बचाव के लिए सार्थक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में देश में 15 साल से बड़ी उम्र की महिलाओं पर न केवल सर्विकल कैंसर का खतरा मंडरा रहा है। बल्कि हर साल 77 हजार महिलाओं की इस बीमारी से मौत हो रही है। यानी हर दिन करीब 211 महिलाएं सर्विकल कैंसर के कारण अपनी जान गंवा रही हैं। साल 2020 में पूरी दुनिया में महिलाओं में सर्विकल कैंसर के 6,04,000 मामले सामने आए, जिनमें से 3,42,000 मरीजों की मौत हो गई। भारत में सर्विकल कैंसर महिलाओं में पाए जाने वाले कैंसर का दूसरा सबसे प्रचलित रूप है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी सर्विकल कैंसर की इसी गंभीरता को देखते हुए अंतरिम बजट में इसके लिए टीकाकरण कार्यक्रम का एलान किया है। उन्होंने देश में नौ से 14 वर्ष की बच्चियों को सर्विकल कैंसर की वैक्सीन दी जाने की बात कही हैं।

सर्विकल कैंसर महिलाओं के लिए गंभीर समस्या है। इससे बचाव के लिए सार्थक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है

मेडिकल जर्नल 'द लेंसेट' की एक रिपोर्ट की मानें तो दुनिया में सर्विकल कैंसर से पीड़ित महिलाओं की मौत के मामले में भारत पहले नंबर पर है। दुनिया में हर पांच में से एक सर्विकल कैंसर से ग्रस्त महिला भारतीय है। हमारे देश में सिर्फ एक प्रतिशत महिलाओं की सर्विकल कैंसर की जांच हो पाती है जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि कम से कम 70 प्रतिशत महिलाओं की टेस्टिंग होनी चाहिए।

ब्रेस्ट कैंसर हो या सर्विकल कैंसर महिलाओं के लिए, दोनों ही बीमारियां जानलेवा साबित हो रही हैं। महिलाएं सामाजिक तौर पर इस बीमारी के बारे में बात करने में शर्म महसूस करती हैं। सरकार द्वारा भी पूर्व में इसे लेकर उतनी गंभीरता नहीं दिखाई गई, लेकिन अब उसने प्राथमिक स्तर पर जागरूकता लाने के लिए कदम उठाने का निर्णय लिया है। डाक्टरों की मानें तो सही समय पर जागरूकता और सही इलाज से महिलाओं की जान बचाई जा सकती है। इस वक्त सर्विकल कैंसर से पीड़ित महिलाओं को नया जीवन कैसे मिल सकता? इस पर चर्चा होनी चाहिए। महिलाओं को असुरक्षित यौन संबंधों से बचने की भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक से अधिक पार्टनर होने से सर्विकल कैंसर का खतरा बढ़ता है। इसके अलावा सरकार को जांच का दायरा बढ़ाने की भी आवश्यकता है, क्योंकि सिर्फ एक प्रतिशत महिलाओं की जांच होने से समस्या से छुटकारा नहीं पाया जा सकता है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

29 फरवरी के बाद भी इस्तेमाल कर सकेंगे पेटीएम वालेट में जमा पैसा

हाल ही में आरबीआइ ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक (पीपीबीएल) से कहा है कि वह 29 फरवरी से अपने बैंक खातों में किसी भी प्रकार का जमा नहीं स्वीकार कर सकेगा। साथ ही प्री-पेड इंस्ट्रूमेंट्स, वालेट, नेशनल कामन मोबिलिटी कार्ड, फास्टैग आदि में टाप-अप या किसी भी प्रकार का जमा संबंधी लेनदेन नहीं किया जा सकेगा। आरबीआइ की इस सख्ती के बाद उपभोक्ताओं के सामने कई तरह से सवाल उठ रहे हैं। आइए आपके बताते हैं कि पीपीबीएल संकट का ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा और उनके पास क्या विकल्प हैं...

पेटीएम पेमेंट्स बैंक क्या है?

पेटीएम पेमेंट्स बैंक एक डिजिटल बैंक है और यह वन97 कम्युनिकेशंस का एसोसिएट है। वन97 कम्युनिकेशंस पेटीएम नाम से डिजिटिल पेमेंट प्लेटफार्म का संचालन करती है। विजय शेखर शर्मा वन97 कम्युनिकेशंस के संस्थापक है। पीपीबीएल में वन97 कम्युनिकेशंस की 49 प्रतिशत और विजय शेखर शर्मा की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है। पीपीबीएल ने एक बैंक के तौर पर 23 मई 2017 को अपना संचालन शुरू किया था। पीपीबीएल डिजिटल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसमें बचत खाता, चालू खाता, भागीदार बैंकों के साथ मिलकर फिक्स्ड डिपाजिट जैसी सेवाएं शामिल हैं। इसके अलावा यह वालेट, यूपीआइ और फास्टैग जैसी अन्य सेवाएं भी देता है। पीपीबीएल के तहत काम करने वाला पेटीएम वालेट डिजिटल पेमेंट सेगमेंट में शीर्ष पर है। आरबीआइ के डाटा के अनुसार, पेटीएम वालेट उपयोगकर्ताओं ने दिसंबर 2023 में 24.72 करोड़ लेनदेन के जरिये आठ हजार करोड़ रुपये की वस्तुओं की खरीदारी की।

उपभोक्ताओं पर क्या असर पड़ेगा?

आरबीआइ ने 29 फरवरी के बाद पीपीबीएल को किसी भी प्रकार की जमा स्वीकार करने से रोक लगाई है। लेकिन ग्राहक बचत खाते, चालू खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, फास्टैग, नेशनल कामन मोबिलिटी कार्ड में जमा पूरी राशि को बिना किसी रोक-टोक इस्तेमाल कर सकेंगे। पेटीएम वालेट ग्राहक अपने वालेट में मौजूद जमा खत्म होने तक 29 फरवरी के बाद भी लेनदेन कर सकेंगे। इस तारीख के बाद पेटीएम वालेट में कोई भी राशि जमा नहीं हो सकेगी। यह नियम पीपीबीएल के खातों और पेटीएम वालेट से जुड़े फास्टैग, नेशनल कामन मोबिलिटी कार्ड पर लागू होगा।

उपभोक्ताओं के पास क्या विकल्प?

इस समय 20 से ज्यादा बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान वालेट की सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें मोबिक्विक, फोनपे, एसबीआइ, आइसीआइसीआइ बैंक, एचडीएफसी बैंक और एमेजोन पे प्रमुख हैं। इसी तरह से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के 37 बैंक फास्टैग की सुविधा दे रहे हैं। उपभोक्ता अपने फास्टैग या डीटीएच को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या गूगलपे, फोनपे जैसे थर्ड पार्टी एप से रिचार्ज कर सकते हैं। बिजली, पानी समेत अन्य प्रकार के बिल भी इन तरीकों से जमा किए जा सकते हैं।

आरबीआइ ने क्यों की कार्रवाई?

आरबीआइ पीपीबीएल के सामने लगातार विभिन्न मुद्दे उठा रहा था। सूत्रों के अनुसार, मनी लांड्रिंग संबंधी चिंताओं और पेटीएम वालेट व इसके बैंक के बीच सैकड़ों करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन के कारण आरबीआइ की यह कार्रवाई करनी पड़ी है। सूत्रों के अनुसार, पीपीबीएल में लाखों खाते बिना केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) नियमों का पालन खोले गए। इन खातों के जरिये करोड़ों रुपये का लेनदेन किया गया है जो प्री-पेड इंस्ट्रूमेंट की तय सीमा से कहीं अधिक है। इससे मनी लांड्रिंग की चिंता बढ़ रही है।

मौजूदा डाटा से ही चुने जाएंगे सूर्योदय योजना के लाभार्थी

तीन सौ यूनिट मासिक खपत वालों को मुफ्त दिए जा सकते हैं उपकरण

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: एक करोड़ घरों की छत पर सोलर प्रणाली लगाने की सरकारी योजना सूर्योदय की घोषणा पर अमल करने का रोडमैप बन रहा है। सरकार के पास अपने आंकड़े हैं और इनके आधार पर ही आगे बढ़ा जाएगा। योजना के लिए उन घरों का खासतौर पर चयन किया जाएगा, जहां हर माह तीन सौ यूनिट की बिजली की औसतन खपत होती है। योजना को इस तरह से अंतिम रूप दिया जाएगा कि कुछ दूसरे मंत्रालयों और निजी सेक्टर की भागीदारी हो, ताकि सौर ऊर्जा पैनल लगाने का व्यापक इस्तेमाल हो।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के अधिकारियों ने बताया है कि सूर्योदय योजना देश में सौर ऊर्जा का आम घरों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल का एक रोडमैप देगी। सरकार का सोच है कि पहले इसका दायरे में मध्यम वर्ग के वैसे घर शामिल हों, जहां अभी भी बिजली की खपत कम है। यही वजह है कि एक महीने में तीन सौ यूनिट खपत वाले घरों का चयन किया जाएगा। यह भी विचार चल रहा है कि इन घरों को सौर ऊर्जा उपकरण पूरी तरह से मुफ्त दिए जाएं। मौजूदा योजना में सरकार 20 से 40 प्रतिशत तक सब्सिडी देती है। सौर प्रणाली लगने के बाद इन घरों में इलेक्ट्रिक उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ने की संभावना को देखते हुए सरकार दूसरी एजेंसियों को भी इस योजना में शामिल करने को सोच रही है। जैसे इलेक्ट्रिक चूल्हा बनाने वाली कंपनियां इसमें शामिल होकर आसान किस्तों पर चूल्हे दे सकें।

- सौर ऊर्जा की मौजूदा योजना से पूरी तरह अलग होगी नई योजना
- मौजूदा योजना में 20-40 प्रतिशत तक सब्सिडी देती है सरकार

18 हजार करोड़ रुपये की सालाना बचत का अनुमान

22 जनवरी, 2024 को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पीएम नरेन्द्र मोदी ने सूर्योदय योजना की घोषणा की थी। उसके बाद एक फरवरी को अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका एलान किया था। अपने बजट अभिभाषण में वित्त मंत्री ने कहा था कि इससे सालाना 15 से 18 हजार करोड़ रुपये की बिजली की बचत की जा सकती है। उन्होंने इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने और मैन्यूफैक्चरिंग व इनके इंस्टालेशन में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होने की बात कही थी।

अतिरिक्त अंगुलियां होने का सामने आया राज

शोध ▶ मैक्स नामक एक विशिष्ट जीन में म्यूटेशन को पाया गया है इस जन्मजात विकार का कारक

इस विकार से मस्तिष्क विकास का भी होता है संबंध

लंदन, आइएएनएस : कुछ जन्मजात विकृतियां जब-तब सामने आती रहती हैं। उसके बारे में कई तरह की सामाजिक-सांस्कृतिक धारणाएं भी हैं। उन विकृतियों को कभी दैवीय प्रकोप या फिर सौभाग्य और आशीर्वाद भी माना जाता है। इन्हीं विकृतियों में से एक है हाथ-पैर में अतिरिक्त अंगुलियां होना। मतलब पांच से अधिक अंगुलियां होना। अब शोधकर्ताओं ने एक दुर्लभ विकार की पहचान की है, जिसके कारण बच्चे हाथ-पैर में अतिरिक्त अंगुलियों और कई प्रकार के जन्मजात दोषों के साथ पैदा होते हैं। वैसे तो इस विकार को अभी तक कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन यह पता चला है कि यह मैक्स (एमएएक्स)

इस विकार की हो सकेगी रोकथाम।

नामक जीन में आनुवंशिक उत्परिवर्तन (जेनेटिक म्यूटेशन) के कारण ऐसा होता है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी आफ लीड्स के शोधकर्ताओं की एक टीम ने बताया है कि अतिरिक्त अंगुलियां (पालीडेक्टाइली) मस्तिष्क विकास से संबंधित आटिज्म जैसे कई लक्षणों को भी जन्म देता है।

शोधकर्ताओं का दावा है कि पहली बार इस आनुवंशिक लिंक की पहचान की गई है। इसमें एक अणु पाया गया है, जिसका उपयोग संभावित रूप से कुछ न्यूरोलाजिकल लक्षणों के इलाज और उनकी स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए किया जा सकता है। हालांकि, इलाज के लिए इसका उपयोग करने से पहले इस अणु का परीक्षण करने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। तीन व्यक्तियों पर केंद्रित यह नया शोध द अमेरिकन जर्नल आफ ह्यूमन जेनेटिक्स में प्रकाशित किया गया है। इन व्यक्तियों में शारीरिक लक्षणों का एक दुर्लभ संयोजन पाया गया। उनमें अतिरिक्त अंगुलियों के अलावा सिर की परिधि भी औसत से बहुत बड़ी (जिसे मैक्रोसेफली भी कहा जाता है) देखा गया। ऐसे व्यक्तियों में कुछ अन्य लक्षण भी समान होती हैं, जिनमें उनकी आंखों के विकास में देरी भी शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप जीवन के आरंभ में उनमें दृष्टि संबंधी समस्याएं होती हैं।

शोधकर्ताओं ने इन व्यक्तियों के डीएनए के तुलनात्मक अध्ययन में पाया कि उन सभी में साझा आनुवंशिक उत्परिवर्तन (जेनेटिक म्यूटेशन) है, जो उनके जन्मजात दोषों या विकारों का कारण बनता है। लीड्स यूनिवर्सिटी के डा. जेम्स पाल्टर के मुताबिक, वर्तमान में इन रोगियों के लिए कोई इलाज नहीं है। इसका मतलब है कि इन दुर्लभ स्थितियों पर यह शोध न केवल इसे बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उसके इलाज के संभावित तरीकों की पहचान करने के लिए भी अहम है। इस मामले में एक ऐसी दवा मिली है, जो अन्य विकार के लिए परीक्षणों में है - जिसका अर्थ है कि इन रोगियों को तेजी से ट्रैक कर सकते हैं, यदि यह पता चलता है कि दवा म्यूटेशन के कुछ प्रभावों को उलट देती है।

ऐसे विकारों से बचने का मिल सकता है उपाय

डा. पाल्टर ने बताया कि समान लक्षणों के संयोजन वाले अन्य रोगियों का परीक्षण यह देखने के लिए किया जा सकता है कि क्या उनके पास वही वैरिएंट है, जिसकी पहचान इस अध्ययन में की गई है। बच्चे को ऐसे विकारों के इलाज के लिए पहली बार डाक्टर के पास जाने से लेकर उसका निदान पाने तक में 10 साल से भी अधिक समय लग सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे रोगियों और उनके परिवारों को उनकी स्थिति का कारण पता चले - और यदि वे अपने आनुवंशिक निदान के आधार पर इलाज करा सकते हैं तो उनका जीवन बदल सकता है। शोधकर्ता अब इसकी संभावना तलाश रहे हैं कि इलाज से म्यूटेशन के कारण होने वाले लक्षणों में सुधार होता है या नहीं।

महिलाओं को अधिक महसूस होता है दर्द

नई दिल्ली, प्रेट्र : यह जानकार शायद हैरानी हो सकती है कि बुढ़ापे में दर्द के अहसास में भी लैंगिक भेद होता है। एक नए शोध में बताया गया है कि वृद्ध महिलाओं को दर्द अधिक महसूस होता है और इसके कारण होते हैं- उम्र बढ़ने के साथ उनके मस्तिष्क में होने वाले विशिष्ट परिवर्तन। यह भी पाया गया है कि इन बदलावों से वृद्ध महिलाओं की दर्द के प्रति संवेदनशीलता उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में बढ़ जाती है और इसलिए उन्हें अधिक दर्द का अनुभव होता है।

शोधकर्ताओं के मुताबिक, ये लिंग-विशिष्ट परिवर्तन न केवल किसी के जैविक लिंग से संबंधित हो सकते हैं, बल्कि दर्द के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों से भी जुड़े हो सकते हैं। अमेरिका की ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अन्य शोधार्थियों के साथ मिलकर इस समस्या को लेकर लैंगिक आधार पर पड़ताल की है।

ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में नर्सिंग कालेज में सहायक प्रोफेसर और द जर्नल

▶ बढ़ती उम्र के साथ महिलाओं के मस्तिष्क में होता है विशिष्ट बदलाव

▶ इससे पुरुषों की तुलना में अधिक सिरदर्द से पीड़ित होती हैं महिलाएं

मस्तिष्क में बदलाव से तय होता है दर्द का अहसास। प्रतीकात्मक

आफ पेन में प्रकाशित इस अध्ययन की प्रमुख लेखिका मिशेल फैला के मुताबिक, मस्तिष्क के कौन से क्षेत्र दर्द के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, इसकी पहचान पहले 18 से 40 वर्ष उम्र वर्ग के लोगों में की गई। उसके बाद यह समझने की कोशिश की गई कि 30 से 90 वर्ष की उम्र के बीच क्या होता है, क्योंकि तभी लोगों को क्रानिक दर्द का अनुभव होने लगता है।

अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने 30-86 वर्ष उम्र की 27 महिलाओं और 32 पुरुषों को शामिल किया, जो बढ़ती गर्मी का सामना कर रहे थे। उन्हें यह रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था कि वे गर्मी में कब कमजोर और मध्यम स्तर का दर्द हुआ और प्रत्येक स्तर की अप्रियता को रेट करने के लिए कहा गया।

टीम ने मस्तिष्क क्षेत्रों के केंद्र का निरीक्षण करने के लिए कार्यात्मक एमआरआइ (फंक्शनल एमआरआइ) इमेजिंग का उपयोग किया, जो दर्द के समय उसके अनुभव में एक साथ काम करते हैं। इसमें अवरोही (घटते) दर्द नियामक प्रणाली (डीपीएमएस) भी शामिल है, जो ओपिओइड रिसेप्टर्स को ट्रिगर कर दर्द को कम करने में मदद करते हैं। उन्होंने पाया कि मध्यम दर्द स्तर पर, पुरुषों में अधिक उम्र के साथ डीपीएमएस प्रतिक्रिया में वृद्धि (दर्द के अनुभव होने में कमी) देखी गई, जबकि महिलाओं की उम्र बढ़ने के साथ, डीपीएमएस प्रतिक्रिया में कमी (अधिक दर्द महसूस होना) देखी गई।

प्रतिस्पर्धा पर सोच बदलने की जरूरत

डा. ऋतु सारस्वत

युवाओं की आत्महत्या का कारण उपलब्धि वाली संस्कृति है। यह उन्हें एक मशीन से अधिक कुछ नहीं समझती

'मम्मी-पापा सारी, आइ एम लूजर। मैं जेईई नहीं कर पाई। इसलिए सुसाइड कर रही हूं। यही लास्ट आप्शन है।' इन पंक्तियों के साथ न जाने कितनी पीड़ा लेकर पिछले दिनों एक बच्ची निहारिका ने अपना जीवन खत्म कर लिया। वह कोटा में रहकर एक कोचिंग सेंटर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। कोटा में बीते सप्ताह आत्महत्या की यह दूसरी घटना है। इससे पहले नीट की तैयारी कर रहे मोहम्मद जैद ने आत्महत्या कर ली थी। ऐसा सिर्फ कोटा में ही नहीं हो रहा है। ऐसे हादसे पूरे भारत या कहें विश्व में घटित हो रहे हैं और हम किंकर्तव्यविमूढ़ बने ये सब घटित होते हुए देख रहे हैं। क्या इसके लिए पूरा समाज जिम्मेदार नहीं है? या फिर हम घोर स्वार्थी हो इसे बच्चों की मानसिक कमजोरी मानकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। घर के भीतर और बाहर अनकहे दर्द से भरी तमाम आंखें हमारी ओर देख रही हैं, पर हम अपनी आकांक्षाओं के आगे बच्चों की उस पीड़ा को अल्पकालिक समझ उन पर निरंतर दबाव बनाए जा रहे हैं। जब अभिभावक और समाज बच्चों के जीवन की कीमत पर अपनी महत्वाकांक्षाओं के घोड़े दौड़ा रहा हो तो समझ लेना चाहिए कि यह सामाजिक-सांस्कृतिक विध्वंस की पराकाष्ठा है।

विगत एक दशक में युवाओं की आत्महत्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट बताती है कि भारत में पिछले एक दशक में आत्महत्या करने वाले छात्रों की संख्या में सत्तर प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं अमेरिका में पिछले दो दशकों में युवाओं में आत्महत्या की दर में 62 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। अमूमन सभी देश युवा आत्महत्या के संदर्भ में एक ही पायदान पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। हाल में 'एनल्स आफ पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ' में एक शोध प्रकाशित हुआ, जिसमें बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में गंभीर प्रश्न उठाए गए हैं। इसमें वर्षों तक बच्चों के भीतर पनप रहे अवसाद, चिंता और आत्मघाती विचारों और व्यवहारों की तीव्रता के संबंध में गहन अध्ययन किया गया है। लास एंजिलिस स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की मनोचिकित्सक प्रोफेसर जोसेलीन मेजा कहती हैं कि 'हम व्यक्तिगत स्तर पर लक्षणों को कम करने पर बहुत ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन उन कारणों की अवहेलना कर रहे हैं, जो कि प्रणालीगत हैं। हम वास्तव में सामाजिक संरचनाओं की अनदेखी कर रहे हैं।' यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि आत्महत्या जिसे हम अमूमन 'व्यक्तिगत क्रिया' मानकर विश्लेषित करते हैं वह एक 'सामाजिक क्रिया' है। समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम ने भी अपनी पुस्तक 'सुसाइड' में इस विषय पर गहन शोध के पश्चात यह स्पष्ट किया है कि सामाजिक तानाबाना तथा परिस्थितियां किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए विवश करती हैं।

बच्चों पर न डालें अनावश्यक दबाव। फाइल

अगर इस दृष्टिकोण को केंद्र में रखकर बच्चों के जीवन को करीब से देखा जाए तो कुछ तथ्य स्पष्ट दिखाई देते हैं, जैसे-बच्चे तनाव और अवसाद में हैं। अवसाद कोई बाहरी तत्व नहीं है। यह आंतरिक रूप से शुरू होता है और इसकी जड़ में घोर अकेलापन, लक्ष्यों के प्रति भ्रम और सामाजिक दबाव हैं। बच्चों के भीतर पल रहे अवसाद का केंद्र मूलतः 'उपलब्धि संस्कृति' है, जो इतनी विषाक्त हो चुकी है कि वह बच्चों को एक मशीनी-संरचना से अधिक कुछ नहीं समझती। उपलब्धि वाली संस्कृति उन पर 'सर्वश्रेष्ठ' होने का दबाव बनाती है। यह उन पर प्रतिस्पर्धी दौड़ में सम्मिलित होने के लिए दबाव बनाती है, जहां जीवन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण 'सफलता' है। बच्चों के जीवन की प्रत्येक दिन की गणितीय गणना जिस प्रकार से अभिभावक करते हैं वहां बच्चों के लिए सांस लेने की भी जगह दिखाई नहीं देती। सर्वोच्च उपलब्धि हासिल करने का दबाव बच्चों के संगी-साथी सभी को अलग कर देता है। परिवार और समाज से प्राप्त इस संदेश को बच्चे आत्मसात कर रहे हैं कि उनकी 'उपलब्धियों' के अलावा उनका कोई 'मूल्य' नहीं है।

अभिभावक ही क्यों, संपूर्ण संस्कृति अलग-अलग स्तरों पर एक दबाव समूह की तरह कार्य कर रही है। 'नेवर इनफःव्हेन अचीवमेंट कल्चर बिकम्स टाक्सिक-एंड व्हाट वी कैन डू अबाउट इट' नामक पुस्तक में परिवार, शिक्षकों के साथ-साथ लगभग छह हजार से अधिक माता-पिता से साक्षात्कार के बाद उन तथ्यों को उजागर किया गया है, जिनसे परिचित होना जरूरी हो जाता है। पुस्तक की लेखिका जेनिफर ब्रेहेनी वालेस के अनुसार, 'लगातार अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डालता है। उच्च प्रदर्शन का दबाव सिर्फ माता-पिता का मसला नहीं है, अपितु प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से यह दबाव समाज का बनाया हुआ है।' सबसे दुखद यह है कि व्यवस्थाओं को कोसते अभिभावक यह भूल जाते हैं कि हर बच्चा स्वयं में विशेष है और उसकी अपनी कुछ विशिष्टताएं हैं। यह भी विस्मृत करने योग्य नहीं है कि सफलता खुशी का मापदंड नहीं है। अगर ऐसा होता तो सफल होने का एक तथाकथित मापदंड 'आइआइटी' अपने 33 विद्यार्थियों की पिछले पांच वर्षों में आत्महत्या का साक्षी नहीं बनता। अगर 'धन' वास्तव में संतुष्टि और सफलता का मापदंड होता तो कैलिफोर्निया के पालो आल्टो में युवा आत्महत्या दर राष्ट्रीय स्तर की तुलना में चार गुना अधिक नहीं होती, जहां औसत घरेलू आय दो लाख डालर है। अभी भी समय है कि समाज और अभिभावक अवलोकन करें कि सर्वश्रेष्ठता की जो परिभाषा वे आत्मसात किए बैठे हैं, कहीं वही उनकी सबसे बड़ी असफलता तो नहीं।

(लेखिका समाजशास्त्र की प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

अमेरिका-ब्रिटेन ने हूती क्षेत्रों में हमले किए

आस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड और न्यूजीलैंड ने भी किया सहयोग

वाशिंगटन, 4 फरवरी (भाषा)।

अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं ने शनिवार को यमन में हूती-नियंत्रित क्षेत्रों पर हमले किए। अमेरिका के रक्षा मंत्री लायड आस्टिन ने यह जानकारी दी। आस्टिन ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि ये हमले करने में अमेरिका और ब्रिटेन को आस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड और न्यूजीलैंड से भी सहयोग मिला।

आस्टिन ने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं ने यमन में हूती-नियंत्रित क्षेत्रों के खिलाफ फिर से हमले किए। यह सामूहिक कार्रवाई हूती विद्रोहियों के लिए स्पष्ट संदेश है कि अगर वे अंतरराष्ट्रीय नौवहन और जहाजों पर अपने अवैध हमलों को नहीं रोकेंगे तो उन्हें आगे भी इसी प्रकार परिणाम भुगतने होंगे। हम दुनिया के सबसे महत्त्वपूर्ण जलमार्गों में से एक में जीवन और जहाजों के मुक्त नौवहन की रक्षा करने में नहीं हिचकेंगे। उन्होंने कहा कि इन हमलों का उद्देश्य लाल सागर से वैध तरीके से गुजरने वाले अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय जहाजों पर अस्थिर करने के मकसद से किए जा रहे अकारण हमलों को अंजाम देने की ईरान समर्थित हूती-मिलिशिया (असैनिक लड़ाकों) की क्षमताओं को रोकना तथा कम करना है। आस्टिन ने कहा कि गठबंधन सेना ने हूतियों के हथियारों के जखीरे के केंद्र, मिसाइल प्रणालियों, वायु रक्षा प्रणालियों और रडार से जुड़े 13 स्थानों को निशाना बनाया।

यमन में 13 स्थानों पर 36 ठिकानों पर किए हमले

अमेरिका ब्रिटेन और उसके अन्य गठबंधन सहयोगियों द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि आस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड और न्यूजीलैंड के समर्थन से अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं ने यमन में 13 स्थानों पर 36 हूती ठिकानों के खिलाफ आवश्यक हमले किए। ये हमले अंतरराष्ट्रीय और वाणिज्यिक नौवहन के साथ-साथ लाल सागर को पार करने वाले नौसैनिक जहाजों के खिलाफ हूतियों के निरंतर हमलों के जवाब में किए गए।

अमेरिका, ब्रिटेन और उसके अन्य गठबंधन सहयोगियों द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि आस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड और न्यूजीलैंड के समर्थन से अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं ने यमन में 13 स्थानों पर 36 हूती ठिकानों के खिलाफ आवश्यक हमले किए।

उन्होंने कहा कि ये हमले अंतरराष्ट्रीय और वाणिज्यिक नौवहन के साथ-साथ लाल सागर को पार करने वाले नौसैनिक जहाजों के खिलाफ हूतियों के निरंतर हमलों के जवाब में किए गए। बयान में कहा गया है कि आज के हमले में विशेष रूप से हूतियों के हथियार भंडार केंद्रों, मिसाइल प्रणालियों और लान्चर, वायु रक्षा प्रणालियों और रडार से जुड़े स्थानों को निशाना बनाया गया। वाणिज्यिक जहाजों और नौसैनिक जहाजों पर पिछले साल नवंबर के मध्य से हूतियों के 30 से अधिक हमले एक अंतरराष्ट्रीय चुनौती बन गए हैं।

रूठी कुदरत और टूटती उम्मीद

बर्फ की छीजन और कमी के जो संकेत भारत में स्थानीय स्तर पर दिखाई दिए हैं, वे दुनिया में बड़े स्तर पर पिछले कुछ अरसे से काफी तीव्रता के साथ महसूस किए जा रहे हैं।

अभिषेक कुमार सिंह

पिछले वर्ष जब यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में सर्दियां बिना बर्फ के गुजर रही थीं तो लगा कि बेलगाम कार्बन उत्सर्जन करने और जीवाश्म ईंधन के बेइंतहा इस्तेमाल से जलवायु परिवर्तन की समस्या पैदा करने वाले विकसित देश अपने कर्मों का नतीजा देख रहे हैं। बर्फ नहीं पड़ी, तो यूरोप के बहुतेरे पर्यटन स्थल वीरान हो गए, ग्लेशियर पिघलने लगे और नदियों का जलस्तर कम होने लगा। मगर, हमें अहसास नहीं था कि ऐसा ही कुछ एक वर्ष के अंदर अपने देश में भी देखने को मिलेगा। दिसंबर से लेकर जनवरी के आधे हिस्से तक हालात ऐसे बने कि क्या कश्मीर, क्या हिमाचल और क्या उत्तराखंड, बर्फबारी के मामले में इन सभी राज्यों के पर्वतीय इलाके तकरीबन सूखे ही रहे। इस अवधि में न तो बारिश और बर्फबारी कराने वाले पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए और न ही स्थानीय मौसमी करवट ने कहीं भी ऐसी हलचल पैदा की कि पर्यटकों से लेकर किसानों और कारोबारियों के चेहरे खुशी से खिल जाएं।

बर्फ के इस सन्नाटे को लेकर किसान, मौसम विज्ञानी और अर्थशास्त्री डरे हुए हैं। पर्यटन की आस पर टिके व्यवसायियों का दर्द अलग से है। मौसम विज्ञानियों का आकलन कहता है कि दिसंबर से लेकर जनवरी के महीने में कश्मीर के गुलमर्ग, हिमाचल के शिमला-मनाली और उत्तराखंड के जोशीमठ-औली आदि इलाकों में अमूमन डेढ़ से दो फुट तक बर्फ कई मर्तबा गिरती है। मगर, कड़ाके की सर्दी के बावजूद इन ज्यादातर जगहों पर इस बार एकाध अपवाद को छोड़कर करीब अस्सी फीसद कम बारिश हुई। कश्मीर का जो गुलमर्ग कई फुट बर्फ गिरने के नजारों से अमूमन हर साल आबाद रहता था, इस दफा बीते दिसंबर में एक बार छह इंच बर्फ गिरने के साथ वह लगभग सूखा ही रह गया। बर्फबारी खेती के लिए भी बेहद जरूरी है। कश्मीर और हिमाचल के सेब उत्पादकों के चेहरों पर रौनक बर्फबारी के साथ बढ़ जाती है, लेकिन अबकी बार बर्फ न गिरने से उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं।

पर्वतीय राज्यों के आम लोग और किसान जानते हैं कि बर्फ के सूखे में उनके लिए क्या चेतावनी छिपी है। पर्यटन, खेती-बागवानी और पनबिजली उत्पादन समेत कई क्षेत्रों पर बर्फबारी न होने का बुरा असर पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पहले से ही छीजते ग्लेशियर बर्फ के सूखे में और भी खाली हो जाते हैं। असल में, हर साल होने वाली बर्फबारी से ग्लेशियर को हुए नुकसान की भरपाई (रिचार्ज होने) का एक मौका मिलता है। ये ग्लेशियर ही अपने भंडार की बदौलत पूरे साल नदियों और झरनों को पानी मुहैया कराते हैं। पर अगर एक साल के लिए भी वे बर्फ का अभाव झेलते हैं, तो जमा पानी के उनके भंडार तेजी से खाली हो सकते हैं।

जम्मू-कश्मीर में लद्दाख-कारगिल जैसे इलाकों में बर्फबारी न होने का मतलब है कि हिमालय का यह इलाका सूखे की चपेट में है। इस कारण यहां से निकलने वाली नदियां गर्मी के दिनों में मैदानी इलाकों में

पर्याप्त पानी नहीं ले जा पाएंगी।

हालांकि, ग्लोबल वार्मिंग का असर हिमालयी इलाके पहले से झेल रहे हैं। भूवैज्ञानिक बताते हैं कि नब्बे के दशक में इन ज्यादातर हिमालयी क्षेत्रों में दिसंबर से लेकर जनवरी तक तीन फुट से ज्यादा की बर्फबारी

> **एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2050 तक समुद्र में पिघली बर्फ के कारण पानी की बढ़ी मात्रा से जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को सीमित करने वाली जलधाराओं की प्रवृत्ति उलट सकती है। इसके असर से इंसानी गतिविधियों द्वारा पैदा होने वाले सालाना कार्बन उत्सर्जन के लगभग एक-तिहाई हिस्से को सोख कर जलवायु परिवर्तन को कम करने की महासागर की क्षमता भी लड़खड़ा सकती है। इसलिए जरूरी है कि प्रकृति के इस श्वेतवर्णी वरदान को बचाए रखने के जतन किए जाएं, जो शायद वैश्विक ताप को थामने वाली कोशिशों से कुछ हद तक साकार हो सकते हैं।**

कई बार होती थी। मगर, अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे कम ग्रीनहाउस गैसीय उत्सर्जन करने वाले ये इलाके भी वैश्विक जलवायु परिवर्तन से पैदा हो रही समस्या की चपेट में आ गए हैं। एक दावा है कि बर्फ और बारिश की कमी तथा ग्लोबल वार्मिंग के कारण कश्मीर-लद्दाख के तापमान में चार से सात डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो सकता है, जो यहां की खेती-बागबानी और समूची पारिस्थितिकी को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकता है। बीते कुछ वर्षों में कश्मीर और लद्दाख के किसानों ने पानी की कमी का संकट बार-बार पैदा होने के मद्देनजर अपने धान के खेतों को फूलों के बगीचे में तब्दील कर दिया है, जो यहां की पारिस्थितिकी में बदलाव का संकेत है।

पर्वतीय राज्यों के लिए बर्फ का एक पहलू पर्यटन से भी जोड़ता है। बर्फबारी न होने से उत्तराखंड के मसूरी-नैनीताल की सड़कें पर्यटकों से गुलजार नहीं हो पाई हैं, तो कश्मीर के गुलमर्ग-पहलगाम जैसे इलाकों में भी उम्मीद से काफी कम पर्यटक पहुंच रहे हैं। यही नहीं, रोमांचक पर्यटन के रूप में लोकप्रिय स्नो-स्कीइंग जैसे खेलों के लिए जरूरी बर्फ नहीं मिल पाने से इनसे जुड़े आयोजनों पर भी संकट मंडराने लगा है। पर्यटकों की कम आमद होटल कारोबारियों, टैक्सी चालकों, घोड़ा-खच्चर मालिकों और अन्य व्यापारियों के लिए चिंता की सबब बन गई है।

वैसे बर्फ की छीजन और कमी के जो संकेत भारत में स्थानीय स्तर पर दिखाई दिए हैं, वे दुनिया में बड़े स्तर पर पिछले कुछ अरसे से काफी तीव्रता के साथ महसूस किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर जमी बर्फ के पिघलने की दर को लेकर है। जैसे एक मुद्दा आर्कटिक क्षेत्र में पड़ने वाले ग्रीनलैंड का है। यहां यों तो पूरे साल बर्फ जमी रहती है, लेकिन अध्ययनों में पता चला है कि बीते एक हजार वर्षों की तुलना में पहली बार ग्रीनलैंड अब सबसे ज्यादा गर्म होने की स्थिति में पहुंच गया है। इसका एक असर वर्ष 2019 में ही महसूस किया जा चुका है, जब तथ्यों के आधार पर दावा किया गया था कि आर्कटिक में बर्फ पिघलने के कारण समुद्री जलस्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यहां ज्यादा चिंता की बात यह है कि ग्रीनलैंड के सबसे महत्त्वपूर्ण ग्लेशियर पीटरमान की परतों में गर्मी के कारण तेजी से टूट-फूट हो रही है। इसका नतीजा यह हो सकता है कि पूरी दुनिया में महासागरों का जलस्तर इस कारण बढ़ जाएगा। इससे निचले द्वीपों और तटीय इलाकों के लिए खतरा भी बढ़ जाएगा। उत्तरी ध्रुव की तरह दक्षिणी ध्रुव यानी अंटार्कटिका में आर्कटिक की तुलना में छह गुना ज्यादा बर्फ है। मगर, वर्ष 2022 में यह बर्फ अब तक के सबसे निचले स्तर पर थी।

ध्रुवों पर ग्लेशियर के पिघलने का खतरा कितना गंभीर है, इसका पता विज्ञान पत्रिका 'नेचर' में प्रकाशित एक अध्ययन से चलता है। इस अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2050 तक समुद्र में पिघली बर्फ के कारण पानी की बढ़ी मात्रा से जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को सीमित करने वाली जलधाराओं की प्रवृत्ति उलट सकती है। इसके असर से इंसानी गतिविधियों द्वारा पैदा होने वाले सालाना कार्बन उत्सर्जन के लगभग एक-तिहाई हिस्से को सोख कर जलवायु परिवर्तन को कम करने की महासागर की क्षमता भी लड़खड़ा सकती है। इसलिए जरूरी है कि प्रकृति के इस श्वेतवर्णी वरदान को बचाए रखने के जतन किए जाएं, जो शायद वैश्विक ताप को थामने वाली कोशिशों से कुछ हद तक साकार हो सकते हैं।